ग्रीन रिवोल्ट

हरित-नीरा रहे वसुंधरा

पेजः 4

टीम ग्रीन संस्था द्वारा अपने गो ग्रीन प्रोग्राम के तहत योगदा सत्संग विद्यालय धुर्वा में पौधारोपण किया गया

रविवारीय, 23 - 29 फरवरी 2020 वर्ष- एक, अंक-29, रांची, कुल पृष्ठ 4 हिन्दी साप्ताहिक R.N.I. No. JHAHIN/2019/78094 www.greenrevolt.news मूल्यः 2 रूपये

ग्रीन रिवोल्ट के पाठकों से आग्रह है कि आप पर्यावरण, कृषि, जल संरक्षण, पशुपालन, बागवानी , पेंट्स, वृक्षारोपण से संबंधित खबरें, समस्यायें, लेख,सुझाव, प्रतिक्रियायें या तस्वीरें हमें अवश्य भेजें। हमारा इमेल एवं ह्वाट्सएप नंबर है।

greenrevolt2019@gmail.com

9798166006

भूल सुधार

पिछले अंक में भूलवश बुंडू के सुमानडीह गांव का नाम सुदाम डीह प्रकाशित हो गया था हम अपने पाठकों से इसके लिये क्षमाप्रार्थी हैं। उपरोक्त खबर में गांव का नाम सुदामडीह के बजाय सुमानडीह पढा जाये।

हम फिट रहेंगे तो राज्य और देश भी फिट रहेगा :मुख्यमंत्री

रांची :आज के इस भौतिकतावादी युग में अपने शरीर को चुस्त-दुरुस्त रखना हम सभी के लिए बड़ी चुनौती है। जब हम और आप फिट रहेंगे तो राज्य और देश भी फिट रहेगा। ये बातें मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने मोरहाबादी स्थित बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम में फिट इंडिया रन-ओ-थॉन कार्यक्रम को बतौर मुख्य अतिथि के रुप में संबोधित करते हुए कही। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस तरह के कार्यक्रमों से हमें नई ऊर्जा मिलती है। यह हमें अपने स्वास्थ्य और फिटनेस के प्रति जागरुक करता है। इस तरह के कार्यक्रम का झारखंड में पिछले पांच सालों से लगातार आयोजित होना हम सभी के लिए गौरव की बात है। मुख्यमंत्री ने कहा कि फिट इंडिया का कंसेप्ट झारखंड में तेज रफ्तार से आगे बढ़ेगी।

रन-ओ-थॉन के कई आयाम हैं

मुख्यमंत्री ने कहा कि रन-ओ-थॉन जैसे कार्यक्रमों के कई आयाम होते हैं। इस तरह के कार्यक्रम सिर्फ शारीरिक फिटनेस के लिए नहीं है, बल्कि इससे कई और चीजें भी जुड़ी हुई हैं। इस तरह के आयोजनों से समाज में बेहतर माहौल बनाने का मौका मिलता है। खेलों को बढ़ावा मिलने के साथ इस क्षेत्र में छिपी हुई प्रतिभाओं को सामने आने का मौका मिलता है। फिटनेस के लिए लोगों को जागरुक करने का संदेश मिलता है। इतना ही नहीं, हम सभी में सकारात्मक सोच के लिए भी ताकत भी मिलती है।

पर्यावरण और कृषि को लील रहे हैं क्रशर

मुख्य संवाददाता

रांची : अभी झारखंड सेंट्रल यूनिवर्सिटी के नये परिसर के आस पास पत्थरों की खुदाई का मामला चर्चा में है। युनिवर्सिटी का कहना है कि परिसर के आस पास के चट्टानों, पहाड़ों को बलास्ट करके उड़ाया जा रहा है इससे परिसर के भवनों को तो खतरा है ही इसके अलावा स्टोन डस्ट से परेशानी और आस-पास की खुबसूरती भी तेजी से खत्म हो रही है। चुंकि ये मामला सेंट्रल युनिवर्सिटी से जुड़ा हुआ है और राष्ट्रपति इसके नये भवन का उद्घाटन कर रहे हैं इस लिये यह खबरों में भी आया अन्यथा समूचे झारखंड में पहाड़ों ,चट्टानों को काट कर, बलास्ट कर बेरहमी से सफाचट किया जा रहा है। झारखंड सरकार, पर्यावरण विभाग, खनन विभाग किसी को इस बर्बादी की चिंता नहीं है। उल्टे इसमे सबों का प्रश्रय मिल रहा है। सेंट्रल युनिवर्सिटी के शिकायत और चिंता व्यक्त करने के बाद भी सूचना है कि कैंपस के इर्द गिर्द पत्थर खनन का काम हिंदूकुश कंस्ट्रक्शन कंपनी को और दस साल के लिये मिला है। स्पष्ट है कि सरकार को इससे होने वाले नुकसान से कोई मतलब नही है। पत्थरों को तोड़ने पहाड़ों के खत्म होने से जलसंचयन तो घटता ही है साथ ही पर्यावरण नुकसान और स्टोन डस्ट से आस पास की कृषि योग्य भूमि भी पथरीली एवं बंजर हो जाती है।

ये समस्या बहुत पुरानी है। रामगढ़ जिले में तो दशकों पूर्व भी किसानों ने प्रशासन से इन क्रशर उद्योगों को बंद करने की मांग की थी। किसानों का कहना था कि, एक क्रशर के सात किमी दायरे में आने वाले खेत भी स्टोन डस्ट से पथरीली होकर बर्बाद हो जा रही हैं। वही समस्या आज भी बरकरार है।

रांची आस पास ये हाल तो अन्य जिलों में क्या होगा?

रांची के आस पास पहाड़ों और चट्टानों को क्रशर के लिये काटने का मामला तो अखबारों की नजर में आ गया, लेकिन अंदाजा लगायें कि अन्य सुदूर जिलों में क्या हालत होगी। इसकी बानगी देखनी हो तो लोहरदगा जिले के ही गांवों कस्बों में घूम कर देखा जा सकता है। कई पहाड़ों और चट्टानों को पत्थर के लिये काटा जा रहा है। कई बुजुर्गों से बात करने पर वो बताते हैं कि पहले जिन जगहों पर बड़े चट्टान और पहाड़ थे उनपर चढ कर वो बैठते थे खेलते थे वो जगह अब पूरी तरह से सपाट है या गड्ढे में बदल चुके है। इनमें वैसे तत्व भी शामिल हैं जो पुलिस के साथ मिली भगत कर रात में बारूद लगा कर विस्फोट से चट्टानों को उड़ा दिये और बाद में पत्थरों को गिट्टी बना कर बेचे। ऐसा वाकया गुमला के घाघरा थाने में सालों पहले नदी के आस पास हुआ था और आज भी उन इलाकों में ऐसा हो रहा होगा? इससे इनकार नहीं कर सकते। रांची में तो शहर से सटे एरिया में भी क्रशर उघोग चल रहे हैं।

पहाड़ों की जलसंरक्षण के साथ ही पर्यावरण को बनाये रखने में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इनका सफाया आगे के लिये आत्मघाती है: **डॉ. नितिश प्रियदर्शी**

पत्थरों का भी विकल्प खोजना होगा

पेट्रोल का विकल्प बैट्री और सीएनजी चलित वाहनों के रूप में विकसित किया गया है। वैसे ही ईंटों की जगह अब राख से बनी फ्लाई एश ब्रिक्स उपयोग होने लगे हैं इसे बनाने के लिये खेतों को खोद कर बर्बाद करने की जरूरत नहीं होती। उसी तर्ज पर स्टोन चिप्स का विकल्प खोजा जाना चाहिये ताकि बचे हुये पहाड़ों को संरक्षित किया जा सके। अन्यथा वह दिन दूर नहीं जब अपने खुबसूरत पहाड़ियों और पठारों के लिये जाना जाने वाला झारखंड इनके खनन, क्रशर उघोग और अदूरदर्शिता के कारण सफाचट और बर्बाद हो जाये?

मेकॉन सीएमडी अतुल भट्ट ने किया सोलर पावर प्लांट का उद्घाटन

रांची संवाददाता : भारत सरकार के अभियान हर एक काम देश के नाम के तहत मेकॉन के सीएमडी अतुल भट्ट ने मेकॉन हेड ऑफिस के आईटी बिल्डिंग में शुक्रवार को 40 kWp ग्रिड इंटरैक्टिव रूफटॉप सोलर पावर प्लांट का उद्घाटन चरण -3 के तहत किया जो सालाना 60000 kWh उत्पन्न करेगा। इस अवसर के दौरान निदेशक (तकनीकी) पीके सारंगी, निदेशक (वाणिज्यिक श्री संजय कुमार वर्मा, निदेशक (परियोजनाएं) सलिल कुमार, निदेशक (वित्त) आरएच जुनेजा, मुख्य सतर्कता अधिकारी यू के केडिया और मेकॉन के सभी वरिष्ठ अधिकारी इस अवसर पर उपस्थित थे। मेकॉन पहले ही चरण-1 और चरण-2 के तहत दो 20 'हस्त्र ग्रिड इंटरैक्टिव रूफटॉप सोलर पावर प्लांट स्थापित कर चुका है। इस नवीनतम 40 kWp रूफटॉप सोलर पावर प्लांट के साथ मुख्यालय में कुल स्थापित क्षमता 80 kWp हो गयी है।

सीसीएल का निःशुल्क आईआईटी कोचिंग योजना 2020-22 का प्रवेश पक्रिया प्रारंभ

विस्तृत जानकारी पेज 3 पर देखें

पशुओं के रोगों के उपचार में कमी से देश को हर साल 1.5 लाख करोड़ की हानि

संवाददाता

रांचीः बीएयू में आयोजित उभरते एवं पुनः उभरते पशु रोग पर चर्चा रांची । पशुओं के रोगों के उपचार में कमी से देश को प्रतिवर्ष 1.5 लाख करोड़ की हानि होती है। रोग उपचार में कमी से करीब 30 प्रतिशत पशु उत्पादन में कमी देखी गई है। पशु रोग विशेषज्ञ को पशुओं में रोग आने के बाद उपचार करने की जगह उभरते और पुनः उभरते हुए रोगों पर अग्रिम शोध एवं निदान निकालने की जरूरत है। देश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था में पशुपालन का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए पशु स्वास्थ्य पर राज्यों को विशेष ध्यान दिए जाने की जरूरत है।

ये बातें आईसीएआर, नई दिल्ली के उपमहानिदेशक (पशु विज्ञान) डॉ बीएन त्रिपाठी ने कही। वे 22 फरवरी को बीएयू में आयोजित 'कृषि प्रणाली एवं वन्य जीवन में पशुधन और मुर्गीपालन के उभरते एवं पुनः उभरते रोग के लिए हाल में प्रगति' विषयक दो दिवसीय कार्यशाला के उदघाटन के अवसर पर बोल रहे थे।

मुर्गी रोग के उपचार के लिए टीका का विकास नहीं

डॉ त्रिपाठी ने कहा कि पशुओं के रोगों की चिकित्सा के लिए देश में काफी प्रयास किये गए है। इसके बावजूद मुर्गी के रोग उपचार के लिए अब तक टीका का विकास नहीं किया जा सका है। देश में व्यावसायिक मुर्गी पालन में करीब 2 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गयी है। बेकयार्ड पोल्ट्री फार्मिंग काफी प्रचलित हो रहा है और इसमें करीब 45 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है।

.....शेष पेज तीन पर

सीपीआरएमएसएनई सदस्य बनने की अंतिम तिथि 29 फरवरी तक

रांची :कोल इंडिया की महत्वाकांक्षी योजना 'सेवानिवृत उपरांत अंशदायी चिकित्सा सेवा योजना (संशोधित) (सीपीआरएमएसएनई)' के सदस्य बनने की अंतिम तिथि 29 फरवरी, 2020 तक है। 01 जुलाई, 2016 से पहले जो कर्मचारी सेवानिवृत हो चुंके हैं और अभी तक सीपीआरएमएसएनई के सदस्य नहीं बन पाये हैं वे इस मेडिकल सुविधा का लाभ उठाने के लिए इच्छुक हैं, वैसे सेवानिवृत कर्मचारी 29 फरवरी, 2020 तक स्थानीय सीसीएल प्रबंधन (कार्यरत क्षेत्र) में अपना सदस्यता हेतु आवेदन जमा कर सकते हैं।

सेवानिवृत कर्मचारियों के लिए महत्वांकाक्षी योजना

ज्ञातव्य हो कि सीपीआरएमएसएनई के अंतर्गत लाभार्थी आठ लाख रूपये तक का ईलाज करा सकता है और गंभीर बिमारियों में यह कंपनी नियमानुसार आठ लाख रूपया से भी अधिक हो सकता है। इस मेडिकल सेवा का लाभ उठाने के लिए कर्मचारी को एकमुस्त रू. 40000/- (रूपये चालीस हजार) मात्र (पती/पत्नी दोनों के लिए) स्थानीय प्रबंधन/क्षेत्रीय कार्यालय में जमा करना होगा। सीसीएल की वेबसाईट www.centralcoalfields.in < http://www.centralcoal-fields.in> में जा कर इस योजना की विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

सोशल मीडिया को ही बनाया पर्यावरण सरक्षण का माध्यम

शशिभूषण

रांची : आजकल जिस तरह से पर्यावरण लगातार दूषित होते जा रहा है उसी को मदेनजर रखते हुए कई ऐसे संगठन और लोगों में जागरूकता आते जा रही है । खासकर आज के युवाओं में सोशल मीडिया का क्रेज के साथ- साथ आए दिन पर्यावरण की समस्याओं को देखते हुए उनमें भी संरक्षण करने के लिए कुछ हद तक आगे आ रहे हैं।

पर्यावरण के प्रति अपनी जिम्मेदारी को निभाते हुए राँची कुछ युवा भी ऐसे ही खेल खेल में अपने पास के तालाब को साफ करने का छोटा सा प्रयास का बीड़ा उठाये ।लेकिन उनमें पूरी तरह से आज की जैसे विचारधारा से ओतप्रोत है , या यूं कहें की उन्होंने कैसे योगदान किया? तो इसके लिए सबसे पहले शक्ति सिंह जो एक छात्र है उसने अपने फेसबुक पेज पर डीएवी, बरियातू के पास का एक गंदा से तालाब का वीडियो बनाकर और अपील करते हुए एक चैलेंज दिया इस तालाब में सफाई करने के लिए कोई भी हमारे साथ ज्वाइन करना चाहता है तो आ सकते हैं। इसी क्रम में एक से तीन और दोस्त शामिल हो गये ,और फिर क्या था उसके बाद लगातार 3 दिनो तक 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद इन युवाओं के माध्यम से तालाब जो दिखने में दूषित लग रहा था उसमें थोड़ा कमी आई, इसमे शक्ति सिंह के साथ देने वाले में आकाश महापात्रा,बॉबी और अभय शामिल थे। हालांकि इन दोस्तों ने ये सब करके आगे भी अपनी सहभागिता बढ़ाना चाहते है।

झारखंड के 14.36 लाख किसान लाभान्वित

राजेश कुमार

- **देश के 8 करोड़ 46 लाख से अधिक किसानों को शामिल किया गया**
- **केंद्र सरकार हर वर्ष तीन किश्तों में 6000 रुपये देती है किसानों को**

नई दिल्ली : प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) योजना की 24 फरवरी, 2020 को प्रथम वर्षगांठ है। इस योजना का शुभारंभ देश भर के सभी खेतीहर किसानों के परिवारों को आय सहायता प्रदान करके किसानों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से किया गया था, ताकि उनकी कृषि और संबद्ध गतिविधियों के साथ-साथ घरेलू व्यय की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। इस योजना के तहत प्रति वर्ष 6,000 रुपये की राशि को 2000 रुपये की तीन मासिक किस्तों में प्रत्येक चौथे माह किसानों के बैंक खातों में सीधे हस्तांतरित किया जाता है। उच्च आय की स्थिति से संबंधित मामले अपवाद के रूप में कुछ मानदंडों के अधीन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस योजना का औपचारिक रूप से शुभारंभ 24 फरवरी, 2019 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में एक भव्य समारोह के साथ किया था।

यह योजना एक दिसंबर, 2018 से प्रभावी है। पात्रता के संबंध में लाभार्थियों की पहचान के लिए समय सीमा तिथि एक फरवरी, 2019 थी। लाभार्थियों की पहचान का पूर्ण दायित्व राज्य/केंद्रशासित प्रदेशों की सरकारों पर है। योजना के लिए एक विशेष वेब-पोर्टल www.pmkisan.gov.in प्रारंभ किया गया है। लाभार्थियों को वित्तीय लाभ पीएम-किसान वेब-पोर्टल पर उनके द्वारा तैयार और अपलोड किए गए आंकड़ों के आधार पर जारी किए जाते हैं।

इस योजना के तहत प्रारंभ में पूरे देश में 2 हेक्टेयर तक की कृषि योग्य भूमि रखने वाले सभी छोटे और सीमांत किसानों के परिवारों को आय सहायता प्रदान की गई। बाद में एक जून 2019 से इसके दायरे को विस्तारित करते हुए देश के सभी खेतीहर किसान परिवारों को इसमें शामिल किया गया। हालांकि पिछले मूल्यांकन वर्ष में, आयकर अदा करने वाले प्रभावशाली पेशेवर किसानों जैसे चिकित्सकों, अभियंताओं, अधिवक्ताओं, सनदी लेखाकारों और प्रति माह कम से कम 10,000 रुपये के पेंशनभोगियों (एमटीएस/चतुर्थ श्रेणी/ समूह घ कर्मचारी को छोड़कर) को इस योजना से बाहर रखा गया है। पूर्वोत्तर राज्यों के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं, जहां भूमि स्वामित्व के अधिकार समुदाय आधारित हैं, वन निवासी और झारखंड, जिनके पास भूमि के अद्यतन रिकॉर्ड और भूमि हस्तांतरण पर प्रतिबंध नहीं है।

नामांकन के लिए, किसान को राज्य सरकार द्वारा नामित स्थानीय पटवारी/राजस्व अधिकारी/नोडल अधिकारी(पीएम-किसान) से संपर्क करना होगा। किसान पोर्टल में फारमर्स कॉर्नर के माध्यम से अपना स्व-पंजीकरण भी करा सकते हैं। पोर्टल में फारमर्स कॉर्नर के माध्यम से किसान अपने आधार डेटाबेस कार्ड के अनुसार पीएम-किसान डेटाबेस में अपने नाम में सुधार कर सकते हैं। पोर्टल में फारमर्स कॉर्नर के माध्यम से किसान अपने भुगतान की स्थिति भी जान सकते हैं। लाभार्थियों के ग्राम-वार विवरण भी फारमर्स कॉर्नर पर उपलब्ध हैं।

कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) को भी शुल्क के भुगतान पर योजना के लिए किसानों के पंजीकरण के लिए अधिकृत किया गया है। फारमर्स कॉर्नर पर दी गई उपरोक्त सुविधाएं सीएससी के माध्यम से भी उपलब्ध हैं। कृषि जनगणना 2015-16 के आधार पर, इस योजना के तहत लाभान्वित होने वाले कुल लाभार्थियों की संख्या 14 करोड़ है। पीएम-किसान पोर्टल में राज्य नोडल अधिकारी (एसएनओ) द्वारा पंजीकृत लाभार्थी 4 माह की अवधि से अपने लाभ के हकदार हैं। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने स्थिति सत्यापन के लिए 24 घंटे 7 दिन कार्य करने वाली एक स्वचालित आईवीआरएस आधारित हेल्पलाइन का भी शुभारंभ किया है।

.....शेष पेज तीन पर

पीएम किसान सम्मान निधि योजना की सफलता

20-02-2020 को पीएम-किसान के लाभार्थी राज्यवार /केन्द्र शासित प्रदेशों में लाभांवित किसानों की संख्या

राज्य	किसानों/परिवारों की संख्या	राज्य	किसानों/परिवारों की संख्या
अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	16,521	पुडुचेरी	9,736
आंध्र प्रदेश	51,17,791	पंजाब	22,40,189
बिहार	53,60,396	राजस्थान	52,04,520
चंडीगढ़	423	तमिलनाडु	35,34,527
छत्तीसगढ़	18,80,822	तेलंगाना	34,81,656
दादरा और नगर हवेली	10,462	उत्तर प्रदेश	1,87,64,926
दमन और दीव	3,466	उत्तराखंड	7,01,855
दिल्ली	12,896	पश्चिम बंगाल	--
गोवा	7,248	कुल (1)	8,12,13,267
गुजरात	48,75,048	पूर्वोत्तर के राज्य	
हरियाणा	14,55,118	अरुणाचल प्रदेश	50,823
हिमाचल प्रदेश	8,72,175	असम	27,04,200
जम्मू और कश्मीर	9,34,299	मणिपुर	1,73,789
झारखंड	14,36,023	मेघालय	70,236
कर्नाटक	49,12,445	मिजोरम	67,540
केरल	27,73,306	नगालैंड	1,70,334
राज्य	किसानों/परिवारों की संख्या	सिक्किम	1,372
लक्षद्वीप	-	त्रिपुरा	1,96,767
मध्य प्रदेश	55,19,575	कुल योग (1+2)	8,46,48,328
महाराष्ट्र	84,59,187		
ओडिशा	36,28,657		

E ZONE CARE

Software Problem, Motherboard Chip-Level Repair, Laptop AC Adapter Repair and Replacement, Laptop LCD Screens Repair and Replacement, Dead Laptop Problems, No Display Problem, LCD Dim Display Problem, LCD White Display Problem, BIOS Password Problem, all type of Laptop repair and service

- Repair your laptop with 3-month warranty.

info@ezonecare.in, ezonecare.in
Rospa Tower 3RD Floor, Main Road, ranchi
93108 96575, 70047 69511
Mon - Fri 10:30 am - 7:00 pm
SUNDAY CLOSED

किसानों के लिये काम कर रही है सरकार?

भारत में सरकारों को अक्सर किसान विरोधी ही कहा जाता है और बहुत सारे जानकार ये आरोप लगाते रहे हैं कि किसी भी सरकार के लिये बजट का मतलब शहर और महानगरों का विकास ही होता है। लेकिन वर्तमान केंद्र सरकार को हम कई मायनों में किसानों के लिये हितचिंतक और ग्रामीण क्षेत्रों के लिये गंभीर कह सकते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने ये तय किया है कि फसल बीमा लेना है या नहीं ये किसान खुद तय करेंगे, मोदी कैबिनेट से मिली मंजूरी केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली सरकार की ओर से बुधवार को किसानों के हित में ये बड़ा फैसला लिया गया है। इसके तहत केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को फसल बीमा योजना में संशोधन को मंजूरी दे दी, इसे किसानों के लिये स्वैच्छिक बना दिया गया। ऐसे में अब किसान खुद तय कर सकेंगे कि वह अपनी फसल का बीमा कराना चाहते हैं अथवा नहीं। कृषि मंत्री ने इस संबंध में बताया कि मंत्रिमंडल ने फसल बीमा योजना में संशोधन को मंजूरी दी, इसे किसानों के लिये स्वैच्छिक बनाया गया है।

वहीं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) योजना की 24 फरवरी, 2020 को प्रथम वर्षगांठ है। इस योजना का शुभारंभ देश भर के सभी खेतीहर किसानों के परिवारों को आय सहायता प्रदान करके किसानों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से किया गया था, ताकि उनकी कृषि और संबद्ध गतिविधियों के साथ-साथ घरेलू व्यय की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। इस योजना के तहत प्रति वर्ष 6,000 रुपये की राशि को 2000 रुपये की तीन मासिक किस्तों में प्रत्येक चौथे माह किसानों के बैंक खातों में सीधे हस्तांतरित किया जाता है। उच्च आय की स्थिति से संबंधित मामले अपवाद के रूप में कुछ मानदंडों के अधीन है। इन योजनाओं की सफलता ये अहसास करा रही है कि किसानों के लिये सरकार वास्तव में कुछ ठोस काम कर रही है।

भारत में किसान सदैव हाशिये पर ही रहा है। हम कथा कहानियों में भी किसान को गरीब ही देखते समझते पढते आये हैं। आखिर क्या कारण है कि देश का किसान सदैव दरिद्र ही रहा है। हमारा बजट भी जब पेश होता है तो देशवासी किसानों और ग्रामीण क्षेत्रों के लिये योजनाओं पर संशय जाहिर करते हैं। इसका कारण भी स्पष्ट है कि जब 70 सालों की आजादी के बाद भी किसान सिंचाई और बीज के लिये ही परेशान है। उसकी उपज की वाजिब कीमत नहीं मिल रही तो ऐसे में किसान गरीब ही रहेगा। वर्तमान सरकार कुछ काम करके इस छवि को कुछ हद तक तोड़ती दिख रही है।

शेरों की आबादी का सही आकलन करने के लिए नई विधि, संरक्षण में मिल सकती है मदद

शोधकर्ताओं ने अपने निष्कर्ष में कहा कि पर्यटन के लिए शेरों को लालच देने से उनके प्राकृतिक आबादी के घनत्व पैटर्न को बहुत नुकसान होता है।

भारत में लुप्तप्राय शेरों की निगरानी के लिए एक वैकल्पिक तरीका उनकी संख्या आंकड़ों में सुधार कर सकता है। साथ ही इससे शेरों की संरक्षण नीति और प्रबंधन निर्णयों में मदद मिल सकती है। वन्यजीवों के जानकार केशव गोगोई और भारतीय वन्यजीव संस्थान के सहयोगियों ने शेरों की गिनती के नए तरीके पर ओपन-एक्सेस पत्रिका प्लोस वन में अपने निष्कर्ष प्रस्तुत किए हैं। गुजरात के गिर जंगलों में केवल 50 की संख्या में बचे हुए एशियाई शेरों को संरक्षण के द्वारा बचाया गया था, जिनकी आज अनुमानित संख्या 500 तक पहुंच गई है। हालांकि, मौजूदा निगरानी के तरीके, विशेष रूप से एक तकनीक जिसे (टोटल काउंट्स) कुल गिनती के रूप में जाना जाता है। इस तकनीक में गिनने के दौरान कुछ शेर छूट सकते हैं या उनकी दोबारा गिनती हो सकती है। यह तरीका शेरों के स्थानीय आबादी के घनत्व पर बहुत सीमित जानकारी देता है।

नए अध्ययन में, गोगोई और उनके सहकर्मियों ने एशियाई शेरों की निगरानी के लिए एक वैकल्पिक तरीके का प्रयोग किया है। उन्होंने कंप्यूटर प्रोग्राम का उपयोग करके अलग-अलग शेरों की पहचान करने के लिए मूंछ पैटर्न और शरीर के स्थायी निशानों को पहचान के तौर पर इस्तेमाल किया है। शेरों के आबादी के घनत्व का अनुमान लगाने के लिए एक गणितीय मा-डलिंग विधि के साथ डेटा का विश्लेषण किया जाता है। जिसे स्थानीय तौर पर स्पष्ट रूप से कैप्चर रिकैप्चर के रूप में जाना जाता है। उन्होंने शेरों द्वारा किए जाने वाले शिकार की आबादी का घनत्व और अन्य कारकों का भी आकलन किया जो शेर के आबादी के घनत्व की विस्तृत जानकारी दे सकते हैं। शोधकर्ताओं ने गिर के जंगल में 725 वर्ग किलोमीटर में एक अध्ययन किया, जिसके अंदर 368 शेर देखे गए। इनमें से 67 अलग-अलग शेरों की पहचान की गई, जिसमें प्रति 100 वर्ग किलोमीटर में 8.53 शेरों की आबादी के घनत्व का अनुमान लगाया गया। ऊबड़-खाबड़ या ऊंचे क्षेत्रों के विपरीत समतल घाटी में शेरों की आबादी का घनत्व अधिक पाया गया था और निकटवर्ती स्थलों पर जहां पर्यटक शेरों को देखना चाहते है वहां शेरों को आकर्षित करने के लिए भोजन रखा गया था। ऐसे चारा देना शेर के व्यवहार और सामाजिक गतिशीलता को बाधित करता है। शोधकर्ताओं का सुझाव है कि उनकी वैकल्पिक निगरानी पद्धति का उपयोग शेरों को उनकी सीमा का आकलन करने के लिए किया जाना चाहिए ताकि मौजूदा संरक्षण प्रयासों को अधिक सटीक रूप से उपयोग किया जा सके।

इंसानी जानों को खतरे में डाल अरबों की फसल काट रही हैं कीटनाशक कंपनियां

ललित मौर्य

भारत में इन कम्पनियों द्वारा बेचे गए कुल कीटनाशकों में अत्यधिक हानिकारक कीटनाशकों (एचएचपी) का हिस्सा करीब 59 फीसदी था जबकि उन्होंने ब्रिटेन में सिर्फ 11 फीसदी एचएचपी की बिक्री की थी

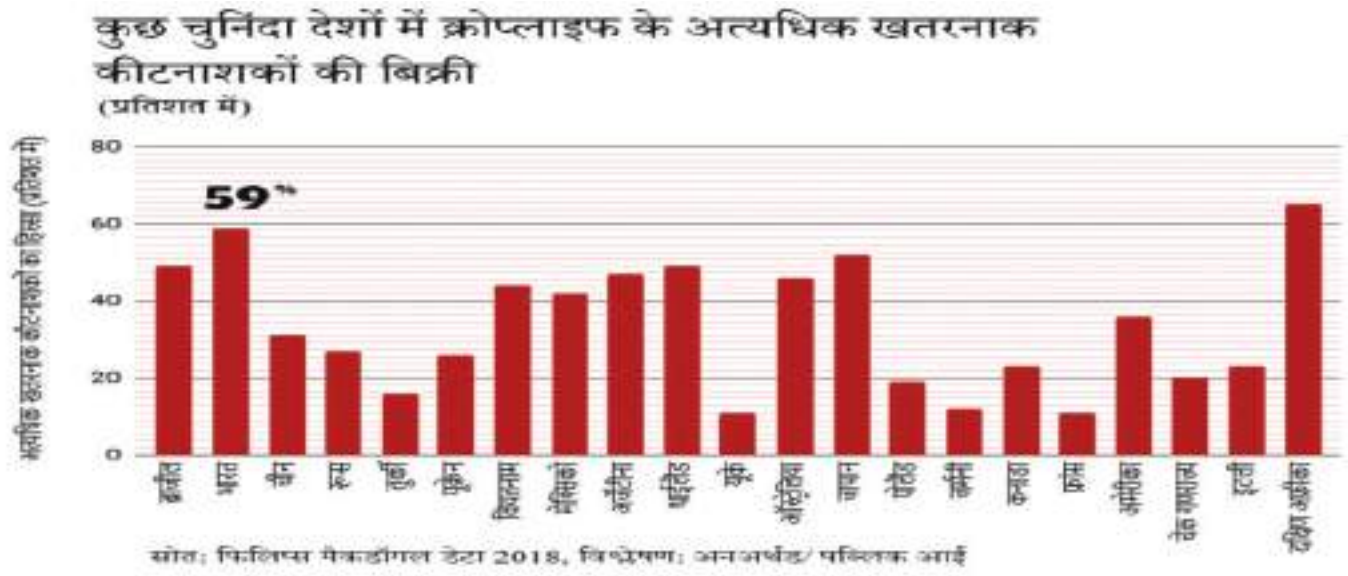

दुनिया की पांच सबसे बड़ी कीटनाशक बनने वाली कम्पनियां अपनी आय का करीब एक तिहाई हिस्सा हानिकारक कीटनाशकों को बेच कर कमाती हैं। यह केमिकल पर्यावरण और स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा हैं। चौंका देने वाला सच दो प्रमुख गैर लाभकारी संस्था अनअर्थड एंड पब्लिक आई द्वारा की गयी संयुक्त जांच में सामने आया है। अध्ययन के अनुसार यह कम्पनियां अपने अत्यधिक हानिकारक कीटनाशकों (एचएचपी) को अधिकतर विकासशील देशों में बेच रही हैं। विश्लेषण के अनुसार जहां भारत में इन कम्पनियों द्वारा बेचे गए कुल कीटनाशकों में एचएचपी का हिस्सा करीब 59 फीसदी था जबकि उन्होंने ब्रिटेन में सिर्फ 11 फीसदी एचएचपी की बिक्री की थी।

यह शोध 2018 के टॉप-सेलिंग क्रॉप प्रोटेक्शन प्रोडक्ट्स के विशाल डेटाबेस के विश्लेषण पर आधारित है। जिसमें उन्होने इन कंपनियों द्वारा 43 प्रमुख देशों में बेचे जाने वाले कीटनाशकों का विश्लेषण किया है। जिससे पता चला है कि दुनिया की प्रमुख एग्रोकेमिकल कंपनियों ने अपनी बिक्री का 36 फीसदी हिस्सा अत्याधिक हानिकारक कीटनाशकों को बेच कर कमाया है। इनके अनुसार इन कंपनियों ने वर्ष 2018 में करीब 34,000 करोड़ रुपये के हानिकारक कीटनाशकों की बिक्री की है। यह हानिकारक कीटनाशक इंसानों के लिए तो नुक्सानदेह हैं ही, साथ ही यह जानवरों और इकोसिस्टम पर भी बुरा असर डालते हैं। यह केमिकल इंसानों में कैंसर और उनकी प्रजनन क्षमता को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इन एग्रोकेमिकल दिग्गजों में बीएएसएफ, बेयर , कोर्टेवा, एफएमसी और सिन्जेंटा शामिल हैं। यह सभी केमिकल इंडस्ट्री के प्रभावशाली समूह क्रॉपलाइफ इंटरनेशनल का हिस्सा हैं।

भारत में इन कंपनियों के केमिकल्स हानिकारक

अध्ययन के अनुसार इनके द्वारा बेचे जाने वाले कुछ कीटनाशक यूरोपीय बाजारों में प्रतिबंधित हैं क्योंकि वो इंसानों और मधुमक्खियों पर बुरा असर डालते हैं। लेकिन विकासशील देशों में लचर कानूनों के चलते यह कंपनियां आराम से अपने केमिकल्स को बेक रही हैं। यही वजह है कि भारत और ब्राजील जैसे देशों में इनकी भारी मात्रा मात्रा बेच दी जाती है। अनुमान है कि भारत में इनके द्वारा बेचे जाने वाले कुल कीटनाशकों में 59 फीसदी कीट्नाशक अत्यधिक हानिकारक की श्रेणी में आते है जबकि ब्राज़ील में 49 फीसदी, चीन में 31 फीसदी, थाईलैंड में 49, अर्जेंटीना में 47 और वियतनाम में 44 फीसदी अत्यधिक हानिकारक श्रेणी के कीटनाशक बेचे जाते हैं। जबकि विकसित और विकासशील देशों के बीच तुलनात्मक रूप से देखें तो इन कंपनियों द्वारा विकासशील देशों में करीब 45 फीसदी अत्यधिक हानिकारक कीटनाशकों की बिक्री की थी। जबकि विकसित देशों में करीब 27 फीसदी एचएचपी की बिक्री की थी।

इस विश्लेषण के अनुसार इन पांच कंपनियों द्वारा बेचे जाने वाले करीब 25 फीसदी कीटनाशक मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं। 10 फीसदी मधुमखियों को नुकसान पहुंचा सकते हैं जबकि इनमे से 4 फीसदी इंसानों के लिए अत्यंत जहरीले होते हैं। गौरतलब है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) और एफएओ द्वारा एचएचपी को अत्यधिक हानिकारक कीटनाशकों के रूप में परिभाषित किया हैं जो मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिए अत्यंत हानिकारक होते हैं। जिसमें पर्यावरणीय खतरों में जल स्रोतों के प्रदूषण, परागण में आने वाली दिक्कतों और पारिस्थितिकी तंत्र पर पड़ने वाले असर जैसी समस्याओं को शामिल किया है। इस खतरे से निपटने के लिए डब्ल्यूएचओ और एफएओ ने न केवल कठोर नियमों की आवश्यकता पर बल दिया है बल्कि उसके क्रियान्वयन पर भी जोर दिया है। भारत में भी हानिकारक कीटनाशक एक बड़ी समस्या हैं 2018 में भारत का कीटनाशक बाजार 19,700 करोड़ रुपये आंका गया है जिसके 2024 तक बढ़कर 31,600 करोड़ रुपये का हो जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। ऐसे में इन हानिकारक कीटनाशकों की बिक्री एक बड़ी समस्या बनती जा रही है। जिससे जल्द निपटने की जरुरत है। इसलिए आगामी कीटनाशक प्रबंधन विधेयक 2020 अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत में कृषि काफी हद तक इन कीटनाशकों पर ही निर्भर है, जिसमें बड़ी मात्रा में ऐसे कीटनाशक शामिल हैं जिनका अत्यधिक उपयोग और दुरुपयोग मनुष्यों, जानवरों, जैव-विविधता और पर्यावरण के स्वास्थ्य पर भारी असर डाल रहा है। ऐसे में इन हानिकारक कीटनाशकों के उपयोग पर लगाम कसना जरुरी है। इसके साथ ही जैविक खेती को बढ़ावा देना एक अच्छा विकल्प हो सकता है

टाटा ट्रस्ट्स का अभियान कचरे को अलग करने के लिए नागरिकों को कर रहा प्रोत्साहित

मुरलीधर

मुंबई : कचरा प्रबंधन की अच्छी आदतों का पालन करने के लिए नागरिकों को प्रोत्साहित करने के बाबत टाटा ट्रस्ट्स ने अपने मिशन गरिमा के तहत TwoBinsLifeWins अभियान की शुरुआत की है। यह अभियान ऐसे बच्चे की कहानी बताता है, जिसके पिता को कचरे को अलग करना पड़ता है, क्योंकि लोग वो काम नहीं करते। यह अभियान लोगों को अपने घरों पर ही कचरे को अलग अलग श्रेणियों में इकठ्ठा करने का संदेश देता है, ताकि सफाई कर्मचारी बेहतर और सम्मानित जिंदगी जी सके। मुंबई के सफाई कर्मचारियों का काम का वातावरण सुरक्षित, स्वस्थ और मानवोचित हो इस उद्देश्य से चलायी जा रही टाटा ट्रस्ट्स की पहल मिशन गरिमा का यह अभियान एक हिस्सा है।

मिशन गरिमा के तहत टाटा ट्रस्ट्स ने कचरा प्रबंधन को अधिक मेकैनिकल बनाने और उस काम में किसी भी व्यक्ति के हाथों का कम से कम इस्तेमाल हो इसलिए टेक्नोलॉजीज उपलब्ध करायी है। टाटा ट्रस्ट्स ने बृहन्मुंबई नगर निगम के सहयोग से 150 से ज्यादा सफाई कर्मचारियों को आधुनिक पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट (पीपीई) दिए हैं। कुर्ला के एल वार्ड में टाटा ट्रस्ट्स और बृहन्मुम्बई नगर निगम द्वारा शुरू की गयी अपनी तरह की पहली मॉडल चौकी में पीपीई के और ज्यादा सेट्स बांटे जाएंगे। चौकियां हर वार्ड में होती हैं, जहां सफाई कर्मचारी अपने रोजाना काम की शुरुआत करने से पहले इकठ्ठा होते हैं और काम खत्म करके वापिस वही पर आकर कपड़ें बदलते हैं। आराम करते हैं। कुर्ला में शुरू की गयी मॉडल चौकी अपने तरह की पहली चौकी है, जिसमें ऑफिस की जगह, पुरुष और महिला कर्मचारियों के लिए अलग-अलग जगहें, पानी और सफाई की बेहतर व्यवस्था, सामान रखने की जगह और मिलने-जुलने, बातचीत के लिए खुली जगह यह प्रावधान मुहैया कराए गए हैं। यहां पानी शुद्ध करने की व्यवस्था, माइक्रोवेव ओवन, जिम और मनोरंजन की अन्य सुविधाएं भी दी जाएंगी।

टाटा ट्रस्ट्स के टाटा वॉटर मिशन के हेड दिव्यांग वाघेला ने बताया कि मुंबई जैसे महानगरों में सफाई कर्मचारी शहर व्यवस्था का बहुत महत्वपूर्ण आधारस्तंभ होते हैं। हमारे शहर को साफ और व्यवस्थित रखने में मदद करते हैं। उनकी सुरक्षा को बरकरार रखने और उनके सम्मान की रक्षा करने के लिए प्रयास करना जरुरी है। सफाई कर्मचारियों के काम के वातावरण में सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए टाटा ट्रस्ट्स ने मिशन गरिमा की शुरुआत की। हमें आशा है कि TwoBinsLifeWins अभियान देशवासियों के विवेक को जागृत करेगा। नागरिकों को अपने घरों में कचरे को अलग-अलग इकठ्ठा करने के लिए प्रोत्साहित करेगा, ताकि सफाई कर्मचारी सम्मानित जीवन जी सके।

इस अभियान को एफसीबी उल्का ने विकसित किया है। अभियान के तहत सुनाई जा रही कहानी के बारे में एफसीबी उल्का के नेशनल क्रिएटिव डायरेक्टर कीगन पिंटो ने बताया कि मन को छू लेने वाली यह फिल्म सच्ची भावनाओं, प्रतिक्रियाओं से प्रेरित है। यह फिल्म हमारे लिए बहुत खास है, लेकिन उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण फिल्म का उद्देश्य और उसमें दिया जा रहा संदेश है। एक आदमी को नाली में नीचे जाकर सफाई करनी पड़ती और इस काम की वजह से वह अपनी जान गवां देता है। उसके बच्चों को अनाथ होना पड़ता है, हमारी भारतीय व्यवस्था में सामूहिक सुविधा और अज्ञान की इससे बुरी, बेहूदा, दुःखद, घिनौनी बात दूसरी नहीं हो सकती। हम चाहते हैं कि यह फिल्म परिवर्तन लेकर आए। हम आशा करते हैं कि लोग घरों में कचरे के दो डिब्बें रखने की छोटी सी आदत को अपनाएंगे और इस प्रथा को जड़ से नष्ट करेंगे।

स्पेस तकनीक से रोकेंगे खेतों के पानी की बर्बादी

खेतों में होने वाली पानी की बर्बादी को रोकने के लिए अब स्पेस तकनीक की मदद ली जाएगी। फसल का तापमान बताएगा कि सिंचाई की अभी जरूरत है या नहीं। आईआईटी कानपुर के वैज्ञानिकों ने पायलट प्रोजेक्ट के तहत कानपुर के गांवों पर एक साल तक शोध किया और डाटा एनालिसिस के बाद एक विस्तृत मैप तैयार किया है।

इसके आधार पर फसलों में पानी की मात्रा तय की जाएगी। आईआईटी कानपुर और लीसेस्टर विश्वविद्यालय यूके के वैज्ञानिक थर्मल इमेजिंग आधारित ड्रोन पर प्रयोग कर रही है। वैज्ञानिकों की टीम संस्थान के नजदीक बनी और बंसेठी गांव में प्रयोग कर रहे हैं।गांव में चल रहे प्रयोग को देखने मंगलवार को आईआईटी व यूके के वैज्ञानिकों के साथ प्रदेश के संयुक्त निदेशक नीरज श्रीवास्तव भी पहुंचे। आईआईटी कानपुर के अर्थ साइंस विभाग के वरिष्ठ प्रोफेसर राजीव सिन्हा ने बताया कि देश में 80 फीसदी पानी का उपयोग खेती में किया जा रहा है, जबकि इसकी जरूरत नहीं है।उन्होंने कहा कि शोध के तहत आईआईटी के वैज्ञानिकों ने खेतों में जाकर मिट्टी से लेकर फसल का तापमान, आद्रता समेत अन्य जरूरी रिकार्ड दर्ज किए गए। प्रो. सिन्हा के मुताबिक दोनों डाटा का एनालिसिस करने के बाद एक मैप तैयार किया गया है। इस मैप के अनुसार अगर खेती की जाए तो पानी की बचत होगी और पैदावार अच्छी होगी। पायलट प्रोजेक्ट में कामयाबी मिलने के बाद इसे वृहद स्तर पर करने की तैयारी है।

मौसम की मार ने बढाई महंगाई

राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक खाद्य पदार्थों विशेष रूप से सब्जियों की बढ़ती कीमतों की वजह से जनवरी 2020 में खुदरा मुद्रास्फीति 68 महीने के उच्चतम 7.59 प्रतिशत पर पहुंच गई है। 12 फरवरी को जारी इन आंकड़ों की वजह से बढ़ती महंगाइ दर ने सबसे अधिक सुर्खियां बटोरीं, लेकिन खाद्य कीमतों में लगातार वृद्धि के पीछे के कारणों की जानकारी जनता को नहीं दी गई। अतिशय मौसम की घटनाओं की वजह से फसल को नुकसान हुआ है और इससे सब्जियों की आपूर्ति उस समय प्रभावित हुई है, जिस समय बाजार में बड़ी तादात में सब्जियां आती हैं। साल-दर-साल की तुलना के आधार पर देखा जाए तो जनवरी 2019 के मुकाबले सब्जियों की कीमतों में 50.19 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

तेजी से घटते जानवरों की आबादी से चिंतित देश

एजेंसियां: गांधीनगर में संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीशीज (सीएमएस) का सम्मेलन 22 फरवरी तक चला। यह प्रवासी प्रजाति के जीवों के संरक्षण का यह 13वां सम्मेलन था। संयुक्त राष्ट्र के 'प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण' पर हो रहे 13वें सम्मेलन में संकल्प लिया गया है कि एशियाई हाथी, जैगुआर, व्हाइट टिप शार्क और कई तरह के पक्षियों को लुप्तप्राय प्रवासी प्रजाति को कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीशीज (सीएमएस) की श्रेणी में शामिल किया जाएगा. लुप्त होने की कगार पर खड़े जीवों की ये प्रवासी प्रजातियां संधि के परिशिष्ट एक में शामिल हैं और इन्हें बचाने के लिए संधि सख्त सुरक्षा प्रदान करता है.

अधिवेशन में इस मुद्दे पर सहमति बनी कि हस्ताक्षर करने वाले देशों को इन जानवरों की हत्या से बचाना होगा। कई और प्रजातियों के जीवों के भी परिशिष्ट दो में शामिल किए जाने की उम्मीद जताई जा रही है जिसके बाद देशों को प्रजातियों की सुरक्षा के लिए और अधिक सहयोग करना होगा।

जानवरों के साथ क्या क्या करते हैं लोग 'स्टेट्स सिंबल'

हाथी दांत, गैंडे के सींग तो थे ही, भालू के पंजे भी कई एशियाई देशों में खाने की खास चीज के तौर पर पेश किए जाते हैं। बहुत दर्दनाक तरीके से भालू का पित्त निकाला जाता रहा है जिसका इंसान के लिए दवाएं बनाने में इस्तेमाल होता है। सीएमएस की सूची वाले जीवों की घटती आबादी के लिए इंसान के हाथों शिकार या फिर प्राकृतिक आवास को नष्ट किया जाना जिम्मेदार है। यूएन के एक शोध का अनुमान है कि आने वाले दशकों में जानवरों और पौधों की लाखों प्रजातियां विलुप्त हो जाएंगी. एशियाई हाथी अपने दांतों की वजह से शिकारियों के निशाने पर हैं। पशु कल्याण विशेषज्ञ राल्फ सोनटाग का कहना है कि जैगुआर पिछले एक सदी में अपने आवास का 40 फीसदी हिस्सा खो चुके हैं वहीं समुद्री व्हाइट टिप शार्क भी शिकार की वजह से लुप्तप्राय शार्क बन गए हैं. इनके पंख का सूप एशिया में खूब पसंद किया जाता है। ●

हाइड्रोपोनिक विधि से खेती कर विख्यात हुए सतारा के सुधीर

एजेंसियां : महाराष्ट्र के सतारा निवासी किसान सुधीर देवकर हाइड्रोपोनिक विधि से खेती कर मालामाल हो रहे हैं। उन्होंने अपने साथी विक्रांत चौधरी के साथ मिलकर हाइड्रोपोनिक्स संयंत्र बनाया। जो बाद में व्यवसायिक रूप से खेती में सफल रहा। अब सुधीर कम लागत में कई गुना कमाई कर लोगों की नजीर बन गए हैं। युवा किसान की इस पहल की सभी सराहना कर रहे हैं।

सुधीर बताते हैं कि जल संकट, बाजार मूल्य में उतार-चढ़ाव, खराब गुणवत्ता के उत्पादन और उर्वरकों, कीटनाशकों की उच्च लागत जैसे मुद्दों का लगातार सामना करने के बाद उनके मन में यह विचार आया। इसके बाद हाइड्रोपोनिक प्रोजेक्ट बनाने पर काम करना शुरू किया। उन्होंने बताया कि वर्तमान में वे केवल 5000 वर्ग फीट क्षेत्र में 50 किलोग्राम मीठे इतालवी तुलसी का उत्पादन कर रहे हैं और बिगबास्केट उनके सबसे बड़े ग्राहक में से एक हैं। कहा कि भविष्य में हम अपने कारोबार को उन शहरों में विस्तारित करेंगे जहां भवन की छत का उपयोग सब्जी उत्पादन के लिए किया जाता है। 24 गुना कम लगता है पानी

सुधीर देवकर बताते हैं कि उनकी इस खेती में उत्पादन के लिए प्रति माह 12000 लीटर पानी का उपयोग होता है। जो कि सामान्य से 24 गुना कम है। उनकी इस विधि में जलवायु परिस्थितियों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। बिना प्रभावित हुए एक ही गति से गुणवत्ता वाली सब्जी का उत्पादन कर रहे हैं। किसान सुधीर ने अपने खेत और इसकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को नियंत्रित करने के लिए इन-हाउस मोबाइल एप्लिकेशन विकसित किया है। वर्तमान में मुंबई, पुणे और बैंगलोर बाजार में 50 से अधिक फसलों और जलवायु पर नजर रखे हैं।

महाशिवरात्रि महोत्सव के अवसर पर एक जोड़ी आदर्श विवाह करायी गई

रांची : 20फरवरी को श्री सर्वेश्वर महादेव शिव बारात आयोजन समिति हेसल, के तत्वावधान में हेसल देवी मंडप रोड स्थित श्री सर्वेश्वर महादेव मंदिर में धुमधाम से एक जोड़ी शादी करायी गई। इस मौके पर विशिष्ट अतिथि महिला विकास मंच के प्रदेश अध्यक्ष निशी जायसवाल, महामंत्री प्रिया कुमारी गुप्ता, प्रवक्ता. मीनु दास गुप्ता, नीलम शर्मा, सहित संस्था के मुख्य संरक्षक लाल संजयनाथ शाहदेव, मुख्य आयोजन प्रभारी बिनोद कुमार साहु, अध्यक्ष नीरज कुमार, महासचिव प्रवीण सिंह, मिडिया प्रभारी शिव किशोर शर्मा आदि-आदि गणमाण्य बन्धुगण मौजुद थे।इस समारोह को सफल बनाने में मुख्यरूप से चन्द्रकान्ता गुप्ता, अंजना प्रियर्दशनी, नीलम किरण, पुष्पा देवी, रिंकी सिंह, इंदु सिंह, उर्मिला देवी, पुष्पा देवी ने महत्वर्पुण भुमिका निभाई।

दो दिलो को मिलाना सबसे बड़ा पुण्य:निशी जायसवाल

ग्रामीण किसान मजदूर विकास समिति की बैठक

रांची : ग्रामीण किसान मजदूर विकास समिति कि एक बैठक रातु रोड लाह कोठी, रिलाईंसफ्रेस के निकट राजेश तिर्की के अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। इस बैठक को समिति के संरक्षक राहुलराज, प्रदेश प्रवक्ता पंकज मिश्रा ने सम्बोधित किया। बैठक में किसान- मजदूर के सर्वांगिण विकास हेतु 10 सुत्री मांगो को लेकर चर्चा कि गई। समिति के अध्यक्ष राजेश तिर्की ने एक -एक कर सभी मांगो को रखा एवं कहा कि सरकार को हमारी सभी माँगो को ध्यान से देखना होगा। उन्होने कहा कि लेबर बाजार को रातु रोड लाह कोठी से आई. टी. आई. हेहल में शिफट किया जा रहा है जिसकी विधिवत घोषणा कर दी जायेगी। इसका सी.ओ हेहल ने समिति को आश्वासन भी दे दिया है। बैठक में अंजली उराईन, प्रेमी कंचन कुजुर, हैदर खान, राजेन्द्र दास, सुरेन्द्र चैधरी, काजल कुमारी, सबिता कुमारी, सुदेश सिंह, अन्य शामिल थी मजदुर उपस्थित थे।

रेलवे ने चलाया विशेष संरक्षा जागरूकता अभियान

रांची : रेल मंडल पर दिनांक 18.02.2020 से दिनांक 27.02.2020 तक विशेष संरक्षा जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है अभियान के अंतर्गत हटिया से मुरी एवं मुरी से हटिया, हटिया से बानो एवं बानो से हटिया, हटिया से सांकी एवं सांकी से हटिया स्टेशनों एवं इनके बीच चलने वाली ट्रेन संख्या 63504 हटिया बर्दवान पैसेंजर, ट्रेन संख्या 68085 खड़गपुर राँची पैसेंजर , ट्रेन संख्या 58663 हटिया साकी पैसेंजर तथा ट्रेन संख्या 58664 सांकी हटिया पैसेंजर ,ट्रेन संख्या 58665 हटिया साकी पैसेंजर एवं ट्रेन संख्या 58666 सांकी हटिया पैसेंजर ट्रेनों में विशेष संरक्षा अभियान चलाकर यात्रियों को जागरूक किया गया । जागरूकता अभियान में समपार फाटक पार करने के नियम, रेलवे पटरी में मोबाइल फोन या हेडफोन लगाकर नहीं चलने, ट्रेन में ज्वलनशील पदार्थ नहीं ले जाने, चलती ट्रेन में नहीं चढ़ने एवं उतरने, पायदान या गेट में खड़ा होकर सफर नहीं करने, बेवजह भीड़ न लगाने, अनजान व्यक्ति से किसी भी तरह के खाद्य पदार्थ ग्रहण नहीं करने, बंद समपार फाटक के नीचे से फाटक ना पार करना , ट्रेन की छत पर ना चढ़ना, एवं अपना उचित टिकट खरीद कर ही यात्रा करने हेतु जानकारी दी गई तथा इस विषय से संबंधित पंपलेट भी वितरित किया गया ।

नही हैं एंटी रेबीज इंजेक्शन, इमली की लकड़ी जला कर देसी इलाज करते हैं

सिदाम /बुण्डू: बुण्डू प्रखण्ड क्षेत्र अंतर्गत गांव के एक पशुपालक के खस्सी को एक कुत्ते ने काट कर घायल कर दिया। पशुपालक एंटी रेबीज टीका के लिए भ्रमणशील पशु चिकत्सा पदाधिकारी डॉ रेखा तेरेसा कुजूर के पास पहुंचता है। डॉ कहती हैं कि एंटी रेबीज टीका हमेशा उपलब्ध नही रहता है, अभी भी नही है।पशुपालक टीका मंगवाने का आग्रह करता है तो डॉ कहती हैं कि ऊपर से आएगा तभी हो पाएगा। बाद में पशुपालक को बाहर से टीका खरीदना पड़ा। एक टीके की कीमत 140 रुपये है।

क्षेत्र में गर्मी का महीना आते ही पशुओं के लिए कुत्ते का आतंक बढ़ जाता है। इस मौसम में अधिकतर खेत खाली रहता है तो पशुओं को चरने के लिए खुला छोड़ दिया जाता है।लोग अपने घरों में रह जाते हैं। मौके का फायदा उठा कर कुत्ते पशुओं पर हमला कर देते हैं। कुत्ता काटने पर पशु चिकित्सक डॉ कुजूर जी कहती हैं कि जख्म को तुरन्त साबुन से धो देना चाहिए। अगर घाव सामान्य है तो 24 घण्टे के अंदर एक एंटी रेबीज टीका देना होता है। यदि गम्भीर जख्म है तो उसके बाद भी कुछ दिनों के अंतराल में दो और टीका दिया जाता है।

गांव में करते हैं देहाती ईलाज

गांव के अधिकतर पशुपालक एंटी रेबीज टीका के चक्कर में पशु चिकित्सक के पास नही जाते हैं। ईमली के लकड़ी को जला कर उसके अंगारे से पशुओं के जख्म को जलाया जाता है। माना जाता है कि इस तरह जलाने से जख्म में मौजूद जहर भी जल जाता है।

झारखंड के 14.36 लाख किसान लाभान्वित

.....पेज 1 का शेष

किसान अपने आवेदन की स्थिति जानने के लिए 1800-11-5526 या 155261 डायल कर सकते हैं। इसके अलावा, किसान अब ईमेल pmkisan-ict@gov.in पर पीएम किसान टीम से संपर्क कर सकते हैं।

राज्य सरकारें किसानों के लिए समय-समय पर शिविरों का भी आयोजन कर रही हैं, ताकि उनके आवेदन विवरणों में सुधार किया जा सके। एक दिसंबर, 2019 को या उसके बाद मिलने वाली सभी किस्तों का भुगतान लाभार्थियों को केवल आधार प्रमाणीकृत बैंक डेटा के आधार पर ही किया जा रहा है, ताकि वास्तविक लाभार्थियों को सुनिश्चित करने के साथ-साथ दोहरे भुगतान से बचा जा सके। असम और मेघालय के अलावा केन्द्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर एवं लद्दाख को 31 मार्च 2020 तक इस आवश्यकता से छूट दी गई है।

केंद्र सरकार अब तक 50,850 करोड़ रुपये से अधिक की धनराशि जारी कर चुकी है। कृषि जनगणना 2015-16 के अनुमानों के आधार पर, योजना के अंतर्गत आने वाले लाभार्थियों की संख्या लगभग 14 करोड़ है। 20 फरवरी, 2020 तक, राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश सरकारों द्वारा पीएम-किसान वेब पोर्टल पर अपलोड किए गए लाभार्थियों के आंकड़ों के आधार पर 8.46 करोड़ किसान परिवारों को लाभ दिया गया है।

इस योजना के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए एक व्यापक निगरानी तंत्र बनाया गया है। केंद्र के स्तर पर योजना में आवश्यक संशोधन के लिए केंद्रीय वित्त, कृषि और भूमि संसाधन मंत्रियों से युक्त एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है। व्यय विभाग (डीईए), कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग (डीएसी एंड एफडब्ल्यू), भूमि संसाधन और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिवों के साथ कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में राष्ट्रीय स्तर पर एक समीक्षा समिति समय-समय पर सदस्यों के रूप में योजना के कार्यान्वयन की समीक्षा और निगरानी करती है। संयुक्त सचिव स्तर के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के तहत केन्द्रीय परियोजना निगरानी इकाई (पीएमयू) इस योजना के कार्यान्वयन और प्रचार आदि की निगरानी करती है। राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों के स्तर पर, नोडल विभाग और पीएमयू योजना के कार्यान्वयन की निरंतर निगरानी करते हैं, जबकि राज्य और जिला स्तर की निगरानी समितियों का भी गठन किया गया है।

सीसीएल का निःशुल्क आईआईटी कोचिंग योजना 2020-22 का प्रवेश पक्रिया प्रारंभ

फार्म जमा करने की अंतिम तिथि 15 मार्च इंजीनियरिंग परीक्षा के विद्यार्थियों के लिए सुनहरा मौका

रांची : सीसीएल की निःशुल्क आईआईटी योजना 'सीसीएल के लाल-लाडली' बैच 2020-22 के लिए पूरे झारखंड में 10वीं में पढ़ रहे जरूरतमंद बच्चों के लिए आईआईटी जेई व अन्य इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी के लिए आवेदन प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गयी है । फार्म जमा करने की अंतिम तिथि 15 मार्च, 2020 है। योजना के अंतर्गत बच्चों को आईआईटीयन फैकल्टी द्वारा निःशुल्क कोचिंग दी जाती है। साथ ही साथ इस योजना के अंतर्गत रांची में निःशुल्क रहने, खाने, स्कूली शिक्षा, शैक्षणिक सुविधाएं भी दी जायेंगी। इस वर्ष आवेदन प्रक्रिया पूर्णतः ऑनलाईन कर दी गयी है जिसे आप घर बैठे ही आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए सीसीएल के वेबसाईट www.centralcoalfields.in <http://www.centralcoal-fields.in> पर जायें या www.cclkelalandlaadli.in< http://www.cclkelaland-laadli.in> से भी किया जा सकता है। आवेदन पूर्णतः निःशुल्क है। योजना के अंतर्गत रांची सहित सीसीएल के तीन क्षेत्रों (ढोरी, बरकाकाना, एनके (डकरा)) में विडियों कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा कोचिंग की सुविधा दी जाती है। ग्रुप 'क' में शामिल होने के लिए माता-पिता/अभिभावकों की कुल वार्षिक आय रू. छः लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए। ग्रुप 'ख' और वीडियों कॉन्फ्रेंसिंग सेन्टर के लिए आय का कोई मापदंड नहीं है।

सीमएडी सीसीएल गोपाल सिंह के कुशल मार्गनिर्देशन में प्रारंभ की गई सीसीएल के इस महत्वाकांक्षी योजना ने साल दर साल नयी उंचाईयां छूते हुये, योजना के अंतर्गत कोचिंगप्राप्त कर रहे सभी विद्यार्थी आज देश के प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग कॉलजों में प्रवेश प्राप्तकर उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं।

इस वर्ष 'सीसीएल के लाल' सिद्धांत शेखर को जेईई मेन्स में 99.25 पर्सेन्टाईल साथ ही बैच के 16 में से 11 बच्चों ने जेईई मेन्स में 90 पर्सेन्टाईल से ज्यादाप्राप्त कर एक बार फिर अपना परचम लहराया है। आर्थिक रूप से कमजोर परिवार के बच्चों के लिए यह एक सुनहरा मौका है और वे ज्यादा से ज्यादा संख्या में भाग लेकर अपनेभविष्य को संवार सकते हैं। किसी भी अन्य जानकारी एवं समस्या के लिए सीएसआर विभाग, सीसीएल, रांची के फोन/मोबाईल नंबर : 06512365580/2360500/8987452551/6205972170 पर सम्पर्क कर सकते हैं।

न्यू ओसिस फाउंडेशन ने किया वस्त्रों और पौष्टिक आहार का वितरण

रांची: 22फरवरी को न्यु ओसीस फाउंडेशन कि ओर से निवारणपुर पुलटोली, बिरसा चैक, हिनु के टोले-मुहल्ले में पौष्टिक आहार व वस्त्र बुढ़े-बुजुर्ग बच्चो के बीच बांटी गई। निदेशक आर. के. साहु ने कहा न्यु ओसीस फाउंडेशन शिक्षा के बढ़ावा के साथ-साथ पर्यावरण, यातायात, खेल-कुद, स्वास्थ शिक्षा के क्षेत्र में कार्य कर रही है। बच्चो के अनिवार्य शिक्षा के लिए यह संस्था रातु टेंडर में विद्यालय स्थापित कर रही है, जिसमें कक्षा छः तक के विद्यार्थियो को बिल्कुल निःशुल्क शिक्षा दी जायगी।वितरण समारोह में मुख्यरूप से संस्था के वोलेन्टियर कोर्डिनेटर अनु अंजली, जगत सिंह, जितेन्द्र राय, दिवाकर राणा व अन्य उपस्थित थे।

मेकॉन ने बांटे हेल्थकेयर एंड न्यूट्रीशनल सप्लीमेंट

रांची संवाददाता : भारत सरकार के पोषण एवं हर काम देश के नाम अभियान के तहत मेकॉन लिमिटेड के सीएसआर विभाग द्वारा श्यामली कॉलोनी के रोज़बड स्कूल में गुरुवार को हेल्थकेयर एवं न्यूट्रिशनल सप्लीमेंटशन प्रोग्राम आयोजित किया गया। कार्यक्रम के दौरान सीएसआर विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे। इस दौरान तीन वर्ष तक एवं तीन से छे वर्ष तक के आयु समूह के लगभग 70 बच्चों को हेल्थकेयर एंड न्यूट्रीशनल सप्लीमेंट दिया गया। मेकॉन के श्यामली कॉलोनी के इस्पात अस्पताल के डॉक्टर एवं पैरा-मेडिकल कर्मचारियों की देखरेख में विटामिन-ए की खुराक 'हेल्थकेयर' के तहत दी गयी साथ ही बच्चों को पोषण संबंधी चीजें जैसे दाल, सत्तू, गुड़, दलिया भी दिया गया।

पशुओं के रोगों के उपचार में कमी से देश को हर साल 1.5 लाख करोड़ की हानि

.....पेज एक का शेष

पोल्ट्री ग्रामीण पोषण एवं आजीविका का प्रमुख साधन है। पशुरोग विशेषज्ञों को मुर्गी के रोग एवं उपचार के लिए अग्रिम उपचार की तलाश करनी होगी।

आईएवीपी पशु स्वास्थ्य को बढ़ावा दे रहा है

डॉ. त्रिपाठी ने कहा कि इंडियन एसोसिएशन ऑफ वेटनरी पैथोलोजिस्टस (आईएवीपी) हर वर्ष गुणवत्तायुक्त पशु रोग विशेषज्ञ के निर्माण एवं सर्टिफिकेशन पर जोर दे रहा है। प्रतिवर्ष करीब 40 पशु रोग विशेषज्ञ को देकर देश में पशु स्वास्थ्य को बढ़ावा दे रहा है। किसानों की आय बढ़ाने की दिशा में पशु स्वास्थ्य पर ध्यान देने की जरूरत है।

विशेष योगदान के लिए सम्मानित

डॉ त्रिपाठी ने पशु रोग चिकित्सा में विशेष योगदान के लिए डॉ एचवीएस चौहान एवं डॉ केके सिंह को सोसाइटी की ओर से लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रदान किया। इस अवसर पर पशु रोग एवं उपचार पर शोध तकनीकी पुस्तक का भी विमोचन किया।

कॉलेज की उपलब्धि बताई

डीन वेटनरी डॉ सुशील प्रसाद ने स्वागत करते हुए रांची वेटनरी कॉलेज का इतिहास और पशुपालन के क्षेत्र में उपलब्धियां बताई। कार्यशाला का संचालन डॉ नंदिनी कुमारी और धन्यावाद डॉ एमके गुप्ता ने किया। कार्यशाला में देश भर के करीब 150 पशुरोग विशेषज्ञ, वैज्ञानिक और राज्य के सभी 24 जिलों के पशु रोग चिकित्सक भाग ले रहे है। मौके पर डॉ आरएस कुरील, डॉ नरेश सूद, डॉ एसके मुखोपाध्याय, डॉ डीएन सिंह, डॉ अनिरुद्ध प्रसाद, डॉ बिपिन बिहारी, डॉ एमएच सिद्दीकी, डॉ अरुण प्रसाद, डॉ एमपी सिन्हा, डॉ एके श्रीवास्तव एवं महाविद्यालय के छात्र भी मौजूद थे।

कोयले की बिक्री व नीलामी के लिए स्टेकहोल्डर्स के साथ हुआ परामर्श

संवाददाता

रांची 23 फरवरी: 70 के दशक में सरकार द्वारा कोयला खानों के राष्ट्रीयकरण के बाद सिर्फ कोल इंडिया लिमिटेड, सिंगरैनी कोलियरीज कम्पनी लिमिटेड जैसी सरकारी स्वामित्व वाली कम्पनियों को खुले बाजार में कोयले की बिक्री का अधिकार है। जिन निजी कम्पनियों के पास कोयला खदानें हैं, वे अपनी खदानों से उत्पादित कोयले का उपयोग सिर्फ स्टील निर्माण, सीमेंट बनाने तथा बिजली उत्पादन के लिए कर सकती हैं।

हाल ही में भारत सरकार ने कोयला ब्लॉक से उत्पादित कोयले को बाजार में बेचने की छुट के साथ नीलामी के लिए पहल की गयी है। कोयला मंत्रालय द्वारा सक्रिय रूप से विचाराधीन 80 कोयला ब्लॉकों की सूची नीलामी हेतु सीएमपीडीआई के वेबसाइट www.coalblockis.cmpdi.co.in पर उपलब्ध है। कोयला ब्लॉक की संभावित सूची में छोटे ब्लॉक भी शामिल हैं जो अपेक्षाकृत छोटे एवं स्थानीय उद्यमियों द्वारा लिए जा सकते हैं। इससे उत्पादित कोयले को वे ब्लॉक के आसपास अथवा नजदीक के छोटे-मझोले स्तर के उद्योगों को बेच सकते हैं। कोयला मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रमुख नियमों एवं शर्तों पर एक चर्चा पत्र प्रकाशित किया गया है जिसे भारत सरकार के कोयला मंत्रालय की वेबसाइट www.coal.nic.inसे डाउनलोड किया जा सकता है। भारत की कोई भी कम्पनी बिना आगामी नीलामी में हिस्सा लेसकती है। इस संबंध में सरकार ने सभी स्टेकहोल्डर्स से नियमों एवं शर्तों संबंधी राय भी मांगी है। 25 फरवरी, 2020 को सीएमपीडीआई में एक बैठक आयोजित की जा रही है ।

एस. भी. पब्लिक स्कूल के विद्यार्थियों का शैक्षणिक भ्रमण

रांची : महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि के अवसर पर राष्ट्रीय कला मंच की ओर से एस भी पब्लिक स्कूल धुर्वा के विद्यार्थियों ने छोटा नागपुर खादी ग्रामोद्योग संस्थान का शैक्षणिक भ्रमण किया।डॉ राजेन्द्र प्रसाद द्वारा स्थापित एव महात्मा गांधी जी के मार्गदर्शन में स्थ।पित की गई इस खादी संस्था में गरीब तबके के लोगों को रोजगार मुहैया कराया जाता है।आजादी के समय में इस आश्रम में क्रातिकारियो द्वारा अंग्रेजों से युद्ध करने के लिए इस आश्रम में रणनीति तैयार की जाती थी एवं यहां पर कई स्वतंत्रता सेनानी आकर ठहरते भी थे। इस अवसर पर झरखण्ड चैम्बर के अध्यक्ष कुणाल आजबानी , छोटा नागपुर खादी ग्रामोद्योग संस्थान के संरक्षक अभय कुमार चौधरी, सचिव भावना देवी ,समाजसेवी राज कुमार पोद्दार, समाजसेवी राजीव रंजन ,समाजसेवी आशुतोष द्विवेदी,समाजसेवी अनुज वर्मा,अनुकूल चौधरी, गौरव अग्रवाल,, स्कूल के प्राचार्य ,अशोक कुमार ,अमित कुमार,मिथिलेश कुमार साथ ही साथ अखिल भारतीय मड़वाडी महिला मंच की भी अन्नू पोद्दार,गीता डालमिया, उषा अग्रवाल, अनुपमा राजगढ़िया आश्रम के सभी प्रतिनिधि उपस्थित थे।ये जानकारी अमित कुमार साहू ने दी।

एसोचैम का नेशनल समिट कम अवाड्र्स ऑन एडुकेशन 2020 आयोजन संपन्न

शिक्षा और कौशल में झारखंड होगा नए आयाम पर : जगनाथ महतो

संवाददाता

रांचीः शिक्षा की ज्योति सदैव जलती रहे , इसी उद्देश्य के साथ शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए एसोचैम के तरफ से नेशनल समिट कम अवाड्र्स ऑन एडुकेशन 2020 का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में गुणवत्ता शिक्षा पर जोर दिया गया एवं शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने पर प्रकाश डाला गया । तथा साथ ही शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वाले संस्थानों को सराहना के तौर पे सम्मनित किया गया ।

कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में विधानसभा अध्यक्ष रविन्द्र नाथ महतो मौजूद रहे । जिन्होंने कहा कि शिक्षा अभियान जैसी योजनाओं की मद्द से सभी तक शिक्षा पहुंचाने की जरूरत है । झारखंड के शिक्षा मंत्री जगनाथ महतो ने कहा कि झारखंड राज्य में शिक्षा के क्षेत्र में सर्वांगीण विकास होगा । उन्होंने कहा कि अपने कार्यकाल में शिक्षा और कौशल के परिपेक्ष में झारखंड को नए आयाम तक पहुचाएंगे।

विशेष अतिथि के रूप में शिक्षा और साक्षरता विभाग के प्रमुख सचिव अमरेंद्र प्रताप सिंह मौजूद रहे । शिखर सम्मेलन में एसोचैम के उप महासचिव सौरभ सान्याल सौरभ सान्याल ने अपने स्वागत भाषण में कहा कि एसोचैम 2025 तक भारत को $ 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ने के लिए शिक्षा, कौशल और आजीविका की ओर संरेखित करने के लिए अभूतपूर्व प्रयास कर रहा है। ऐसोचैम झारखंड के सह अध्यक्ष जतिन त्रिवेदी , शोभियत यूनिवर्सिटी, मेरठ के उप महासचिव कुंवर शेखर विजेंद्र उपस्थित रहे । कार्यक्रम का समापन एसोचैम के क्षेत्रीय निदेशक भरत जायसवाल के धन्यवाद ज्ञापन के साथ हुआ। कार्यक्रम का समापन भरत जायसवाल द्वारा धन्यवाद ज्ञापन के साथ किया गया। उन्होंने उद्योग जगत के लोगों से अनुरोध किया कि वे एसोचैम के साथ आकर एक टास्क फोर्स बनाएं जो झारखंड को देश के एजुकेशन हब में से एक बनाने में एक साथ काम करेगा।

सीएमपीडीआई में एकदिवसीय कार्यशाला और राउंड टेबल डिस्कसन संपन्न

संवाददाता

रांची:सीएमपीडीआई के तत्वावधान में ''कोल बेनिफिसियेशन ऑप्टीमाइजेशन ऑफ क्लीन कोल यील्ड ऐट लोवर ऐश प्रसेंटेज'' विषय पर आयोजित एक दिवसीय कार्यशाला और राउण्ड टेबल (गोलमेज) डिस्कशन (वार्ता) का विधिवत उद्घाटन मुख्य अतिथि कोल इंडिया के निदेशक (तकनीकी) विनय दयाल तथा विशिष्ट अतिथि कोयला मंत्रालय के संयुक्त सचिव एम. नागराजू ने संयुक्त रूप से किया।

इस अवसर पर मुख्य अतिथि दयाल ने कहा कि भारत में कोकिंग कोल का उत्पादन का बहुतायत हिस्सा वाशरी ग्रेड-5 एवं इससे ऊपर का होता है। उच्च राख प्रतिशतता के कारण भारत में उत्पादित कोकिंग कोल का केवल छोटा हिस्सा मेटलर्जिकल सेक्टर (धातु क्षेत्र) में उपयोग हो पाता है और शेष प्रमुख हिस्से को नॉन-मेटलर्जिकल सेक्टर (गैर-धातु क्षेत्र) में मूल्यवान कोकिंग कोल

रिजर्व होने के बावजूद भी उपयोग किया जा रहा है। स्थिति खतरनाक रूप से गंभीर है क्योंकि हम नॉन-मेटलर्जिकल सेक्टर (गैर-धातु क्षेत्र) के लिए मूल्यवान कोकिंग कोल रिजर्व खो रहे हैं। इस कोल रिजर्व का परिष्करण कर हम विदेशी मुद्रा भंडार में आयात के कारण दवाब को कम कर सकते हैं। आगे उन्होंने कहा कि यह कार्यशाला सरकारी विदेशी मुद्रा की बचत में सहायक सिद्ध होगा क्योंकि कोकिंग कोयले के आयात को कम करने हेतु अनुभवी व्यक्तियों को एक मंच प्रदान किया है। हम उपलब्ध संसाधनों के अनुकूलतम पर कार्य करने के लिए कोयला उत्पादकों के साथ वाशरी संचालकों और उपभोक्ता के अधिक एकीकृत जुड़ाव के लिए तत्पर हैं। इस अवसर पर एम0 नागराजू ने कहा कि भारत सरकार ने एक आत्म-निर्भर इस्पात उद्योग बनाने के उद्देश्य से राष्ट्रीय इस्पात नीति 2017 लाई है। इस नीति के तहत वर्ष 2030-31 तक 300 एमटीपीए स्टील का उत्पादन करने का परिकल्पना की गयी है। इसके लिए लगभग 180 एमटीपीए कोकिंग कोल की आवश्यकता होगी। इसमें कम से कम 35 प्रतिशत स्वदेशी कोकिंग कोल का उपयोग करने के लिए दिशा-निर्देश भी दिए गए हैं। हमारे पास लगभग 27.9 बिलियन टन के मध्यम कोकिंग कोयले का पर्याप्त संसाधन है जिसमें 8.5 बिलियन टन के भंडार में 35 प्रतिशत से अधिक की राख की मात्रा के कारण परिष्करण के लिए विचार नहीं किया जा रहा है। कोकिंग कोल के पुनर्वर्गीकरण के कारण वाशरी-5 एवं वाशरी-6 नामक ग्रेड जुड़ने से अब यह स्टील सेक्टर में उपयोग हो रहा है जबकि पहले यह पावर सेक्टर में उपयोग होता था।

इस अवसर पर विशेष आमंत्रित अतिथि सीसीएल के अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक गोपाल सिंह ने कहा कि एक कोकिंग कोल के सीमित भंडार का देश हित में स्टील उद्योग में प्रयुक्त करने का आह्वान किया ।

मरीजो की सेवा सबसे बड़ा धर्म:शिव किशोर शर्मा

रांची : 23 फरवरी को पिस्कामोड़ पेट्रोल पम्प गली, में दो-तीन दिनो से पड़ा अज्ञात युवा मरीज को छात्र क्लब के अध्यक्ष शिव किशोर शर्मा एवं झारखण्ड विकास सेवा भारती संघ के अध्यक्ष विकास कुमार सिंह ने राँची सदर अस्पताल पहुँचाया । सदर अस्पताल के डॉक्टर आजाद के देखरेख में ईलाज शुरू हुआ। विकास कुमार सिंह ने बताया कि अज्ञात मरीज की स्थिति को देखते हुए पण्डरा थाना प्रभारी शशीरंजन कुमार जी को सुचना दी गई और सरकारी एम्बुलेंस बुलाकर मरीज को सदर अस्पताल पहुंचाया गया। पड़ोसी राजकुमारी देवी ने कही पिस्कामोड़ पेट्रोलपम्प गली में उक्त मरीज कई दिनो से पड़ा था और कराह रहा था। मानवता के नाम से मै उसे भोजन देती थी। जे.एम.एम नेता लक्ष्मण मुण्डा ने मरीज का हाल चाल जाना और सहयोग किया। बीमार को अस्पताल पहुचाने में सहयोग करने के लिए पिस्कामोड़ गुरूद्वारा ग्रंथी सरदार बक्सीस सिंह, एम्बुलेंस कर्मी उमेश , विकाश कुमार वेदांत एवं आम जनता के प्रति संस्था ने आभार प्रकट करते हुए शिव किशोर शर्मा ने कहा ऐसे सभी अज्ञात मरीजो को जो लाचार एवं बेसहारा है उसे निःस्वार्थ भाव से मदद करे तथा नजदीकी अस्पताल में पहुँचाने की कृपा करे।

फोटो न्यूज

स्व0 भैरव नाथ महतो स्मृति फुटबॉल प्रतियोगिता सम्पन्न

सिदाम

रांची/सोनाहातू: सोनाहातू प्रखण्ड के लांदुपडीह उच्च विद्यालय के मैदान में स्व० भैरव नाथ महतो स्मृति एक दिवसीय फुटबॉल खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में कुल 16 टीम ने हिस्सा लिया। इसमें लाल बादशाह हजारीबाग की टीम ने ट्राइ ब्रेकर के सहारे जोहार सरना क्लब घुनचा टोला को पराजित कर ख़िताब हासिल किया। विजेता टीम को नगद एक लाख रूपये तथा उपविजेता टीम को नगद 75 हजार रूपये देकर सम्मानित किया गया।इसके अलावे सेमीफाइनल में पहुंचने वाली बाकी दोनों टीमों को 20-20 हजार रूपये देकर पुरस्कृत किया गया। 21 फ़रवरी को आयोजित इस प्रतियोगिता का उद्घाटन लांदुपडीह पंचायत मुखिया फनी सिंह मुंडा, हेसाडीह पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि प्रताप सिंह मुंडा एवं हरिन पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि मनोज सिंह मुंडा के द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। इस आयोजन में मुख्य अतिथि तमाड़ विधायक विकास मुंडा, विशिष्ट अतिथि पूर्व विधायक अमित महतो उपस्थित हुए। मंच पर अनिल सिंह मुंडा, शत्रुघ्न महतो ,हारु सिंह, परमेश्वर राम, फनीभूषण महतो, तुलसी सिंह, गुलाब सिंह मुंडा आदि मौजूद रहे। कार्यक्रम के आयोजन में रामेश्वर महतो उर्फ़ भोलू का अहम योगदान रहा।लांदुपडीह गांव तथा पंचायत के समस्त ग्रामीणों के सहयोग से प्रतियोगिता का सफल आयोजन हुआ।

हेहल अंचल में गैरमजरूआ जमीन बचाने के लिये हुई बैठक

सवाददाता

रांची : 23फरवरी को आदिवासी छात्र संघ उपाध्यक्ष सुरेश टोप्पो की अध्यक्षता में बजरा पहान टोला सरना स्थल में बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में ग्रामवासियो ने कहा रॉची जिला हेहल अंचल के मौजा बजरा खाता न0-113 एवं 119 मौजा बरियातु खाता न0-73 की लगभग-272 एकड़ गैरमजरूआ जमीन पर अवैध कब्जा है। उसे बचाने के लिए बजरा, बड़का टोली, करम कोचा, खखसी टोली, बरियातु, कुम्बा टोली, सरना टोली, सभी गॉव के पहान महतो, धर्म के अगुवा आदिबैठक में हिस्सा लिया। बैठक मे निर्णय लिया गया कि गैरमजरूवा जमीन को बचाने के लिए उपायुक्त रॉची, अनुमण्डल पदाधिकारी रॉची, मुख्यमंत्री झारखण्ड सरकार तथा संबंधित व्यक्तियो को आवेदन दिया जाएगा तथा इसे बचाने के लिए सैवेधानिक तौर पर लड़ाई भी लड़ी जाएगी। इस अवसर पर सभी लोगो ने अपने - अपने विचार भी प्रकट किए। आज कि बैठक में मुख्यरूप से सुरेश टोप्पो, प्रो. सतीश कु0 भगत, उदय मिंज, प्यारू उरॉव, लालू तिर्की , अजय मुण्डा, लाखो भगत, भांदो उरॉव, उपेन्द्र तिर्की, परिया उरॉव, जगत उरॉव, नीली केरकेटा, मुन्नी उरॉव, बसंती देवी, अंजनी मुण्डा, सुखमनी उरॉव, फगनी उरॉव, अर्जुन भगत, एडवर्ड टोप्पो, प्रभा लकड़ा धनिया देवी, बंधनी उरॉव, रिपिया उरॉव तथा सकड़ौ ग्रामीण उपस्थित हुए। यह जानकारी सुरज टोप्पो ने दी।

4.5 फीसदी बढ़ेगा रबी उत्पादन, सुधरेगी ग्रामीण अर्थव्यवस्था: एनबीएचसी

देश में 2019-20 के दौरान रबी फसलों का उत्पादन 4.52 फीसदी बढ़कर 13.42 करोड़ टन पर पहुंच सकता है। नेशनल बल्क हैंडलिंग कॉरपोरेशन (एनबीएचसी) ने अपने रिपोर्ट में कहा कि मिट्टी में अच्छी नमी और उत्तर-पूर्व मानसून सीजन (अक्तूबर-दिसंबर) के दौरान सामान्य से ज्यादा बारिश होने की वजह से उत्पादन में इजाफा होने का अनुमान है। इससे पहले 2018-19 में रबी फसलों का उत्पादन 12.84 करोड़ टन रहा था। रिपोर्ट में कहा गया है कि रबी फसलों का उत्पादन बढ़ने का सीधा असर ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। इसमें सुधार से किसानों की आमदनी पर सकारात्मक असर देखने को मिलेगा। रिपोर्ट के मुताबिक, 2019-20 में गेहूं का रकबा 12.03 फीसदी बढ़कर 3.34 करोड़ हेक्टेयर और उत्पादन 9.01 फीसदी बढ़कर 11.14 करोड़ टन पर पहुंच जाएगा। हालांकि, चावल का रकबा इस दौरान रिकॉर्ड 23.24 फीसदी घटकर 26.1 लाख टन हेक्टेयर रह जाएगा। पिछले साल यह आंकड़ा 34 लाख हेक्टेयर रहा था। इसी तरह, किसानों के गेहूं और दाल उत्पादन पर जोर देने की वजह से इस दौरान चावल उत्पादन में गिरावट देखने को मिलेगी। पिछले साल के 1.43 करोड़ टन के मुकाबले चावल उत्पादन 27.96 फीसदी घटकर 1.03 करोड़ टन रह जाएगा। **दाल उत्पादन में रहेगी गिरावट** : रिपोर्ट में कहा गया है कि 2019-20 में दाल का रकबा 1.86 फीसदी घटकर 1.59 करोड़ टन हेक्टेयर पर पहुंच जाएगा। पिछले साल यह आंकड़ा 1.56 करोड़ हेक्टेयर रहा था। हालांकि, कुल दाल उत्पादन 2.47 फीसदी घटकर 1.52 करोड़ टन रह सकता है। इस दौरान तेलहन का रकबा मामूली 0.87 फीसदी घटकर 79.7 लाख टन और उत्पादन 7.39 फीसदी घटकर 1.01 करोड़ टन रहने का अनुमान है। पिछले साल 1.09 करोड़ टन तेलहन उत्पादन हुआ था। इसके अलावा, ज्वार (24.3 लाख टन), मक्का (82.8 लाख टन) और जौ (18.3 लाख टन) का उत्पादन बढ़ने से 2019-20 में मोटे अनाज के कुल उत्पादन में 4.92 फीसदी की बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। इस दौरान कुल 1.25 करोड़ टन मोटे अनाज का उत्पादन होने का अनुमान है।

जिंदगी मिलेगी दूबारा फाउंडेशन

संवाददाता

जिंदगी मिलेगी दोबारा फाउंडेशन द्वारा मरीजों को झारखंड राज्य सहित उड़ीसा बिहार छत्तीसगढ़ पश्चिम बंगाल तक घर से लाने और पहुंचाने तथा डेड बॉडी को विशेष रुप से बगैर एक पैसा लिए उनके घर तक पहुंचाने का एक काम राजधानी रांची से बेहतर ढंग से संचालित हो रहा है

रांची : इस पुनीत काम को हमारे राज्य के कुछ युवा मिलकर कर रहे हैं जिनमें एक हैं जयप्रकाश सिंघानिया । सिंघानिया व्यापार से जुड़े हैं लेकिन समाज सेवा भी इनका जिद है इनका शौक है और यह समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं इसी क्रम में ग्रीन रिवोल्ट को दिए गए एक साक्षात्कार में उन्होंने बताया कि उड़ीसा राज्य में एक व्यक्ति द्वारा अपने मृत पत्नी को मिलो तक अपने पीठ पर धोकर ले जाने की घटना ने उन्हें इतना ज्यादा परेशान किया कि उन्होंने अपने मित्रों के साथ मिलकर एक ऐसी योजना बनाई जिससे किसी भी व्यक्ति की मौत के बाद उसके परिजनों को आर्थिक कारणों से ऐसी घटना ऐसा किसी प्रकार का असहयोग असुविधा ना हो और उन्हें एक वाहन उपलब्ध करा दिया जाए निश्चित तौर पर यह एक साहसिक प्रयास था और इस दिशा में उन लोगों ने काम आरंभ किया अब तक लगभग 3000 लोगों को जिंदगी मिलेगी दोबारा फाउंडेशन की ओर से बगैर कोई शुल्क लिए राज्य के सबसे बड़े हॉस्पिटल से उनके घर तक पहुंचाया गया है। इसके लिए एक मोबाइल नंबर सभी सार्वजनिक स्थलों पर उपलब्ध है जिसके माध्यम से आप निशुल्क वाहन के लिए आग्रह कर सकते हैं और फाउंडेशन उन्हें वाहन उपलब्ध कराता है उन्होंने बताया कि अब तक 6 एंबुलेंस इस सेवा में काम कर रहे हैं और हमारे 12 लोगों की टीम मॉनिटरिंग करती है साथ ही यह ख्याल रखती है कि सभी को सम्मानजनक और बगैर किसी तनाव के यह सेवा प्राप्त हो सके इस फाउंडेशन में जुड़े 12 युवाओं में सभी का उद्देश्य जनसेवा ही है और जिंदगी मिलेगी दोबारा फाउंडेशन के माध्यम से यह सेवा लगातार जारी है इसमें सक्रिय रूप से आलोक अग्रवाल, अरविंद मंगल, अश्वनी राजगढ़िया हर्षवर्धन ,बजाज जयप्रकाश सिंघानिया, निखिल केडिया, रमन साबू, सौरभ मोदी, विक्रम साबू, विनीत अग्रवाल विपुल अग्रवाल और विवेक बागला सक्रिय भूमिका निभाते हैं साथ ही समाज के सभी वर्गों से जिंदगी मिलेगी दोबारा फाउंडेशन को सहयोग मिलता है

टीम ग्रीन संस्था द्वारा अपने गो ग्रीन प्रोग्राम के तहत योगदा सत्संग विद्यालय धुर्वा में पौधारोपण किया गया

आली गेली तो गोतिया, खाली पीली तो जतिया

छोटानागपुर में एगो बेस कहावत कहल जाएला

आली गेली तो गोतिया
खाली पीली तो जतिया

ईकर माने आगुर राउरे केकरो घर आवत जात हयि तो समझु राउरे उनकर गोतिया हेकी । आउर राउरे केकरो घर खात पियत्थी तो समझल जाय की उनकर जाति कर हेकी। हमर कहेक कर माने छोटानागपुर में एखनो तक जाईत आउर गोतिया कर महातम बेसे ऊंचा है। इकर साबुत राउरे केकरो घर जाएके पाय सकीला । आगुर गोतिया केकरो घर आएं गेलें आउर घर में कोनो घटल हय तो पैंईया या उधरा केईरके भी स्वागत में कोनो कमी नी रहेक देवेल जायला। गोतिया कर आवत कर साथ गोड के रगैद रगैद के धोवेक । मीठा संग पानी या सरबत परोईस के हाल चाल सुख दु:ख बतियाएक पसंद नापसंद के जानेक घर में बेझिझक एकदम दिल से जुड़ाव कर महसूस कराय देवेला। केउ केउ तो आगुर पिएक वाला हयं तो महुआ वाला दारू या हंडिया कर वेवस्था तुरंत करल जायला।मतलब स्वागत में आपन हैसियत कर हिसाब से कोनो कमी नी छोडल जायला। अब आदमी के फुरसत कम होती जायहे से लागिन गोतिया के बहुत कोई समय कम देवैना मुदा महातम में कमी नी आयहे।

गोतिया कर परंपरा कतना पहिले से चलत्थे बताना मुश्किल हय मुदा गोतिया छोटानागपुर में कई तरह कर होवंयना । कोई नावा गोतिया कोई छोटका गोतिया तो कोई बड़का गोतिया। इ तीनों गोतिया कोई खास कारन से जाल जायला। ऐसे तो गोतिया कई तरह कर होवैंना । मुदा एखन हमरे इ तीनों गोतिया कर बारे में चर्चा करब । शादी विवाह लागिन शुरू शुरू आवेक वाला गोतिया के नावा गोतिया कहल जायला। आगुर शादी विवाह कर बात के फाइनल करेक हय तो छोटका गोतिया । सेहे तईर वि-वाह फाइनल होवल कर बाद समाज कर बगरा आदमी खाएक पीएक लागीन जे गोतिया जाल जायला उके बड़का गोतिया कहल जायला। बड़का और छोटका गोतिया कर बेसी प्रचलन उरांव समाज में देखल जाएला ।मुदा छोटा नागपुर में सदाना आउर उरांव समाज गांव में एखनो तक एके परिवार और समाज लेखे पूजा पाठ, काम धंधा , खेती बारी, शादी विवाह ,रिझ रंग सबे बेरा एक दोसर कर पूरक आहयं। बड़का और छोटका गोतिया कर रेवाज दुईयो समाज में हय । मुदा सदाना मनकर गोतिया कर संख्या बहुत जाईत में आईज काईल कम होते जात्थे। ईकर कारन फुरसत कर अभाव या गरीबी के माईन सकीला।

सीआईएसफ के सहयोग से सीसीएल सुरक्षा कर्मियों को प्रशिक्षण

संवाददता

रांची :सीआईएसफ के सहयोग से सीसीएल सुरक्षा कर्मियों को सुरक्षा संबंधी प्रशिक्षण

सीसीएल के सीएमडी गोपाल सिंह के मार्गनिर्देशन में सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड (सीसीएल) ने सीआईएसएफ के सहयोग से सीसीएल के सुरक्षा गार्डस को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रथम चरण में सुरक्षा कर्मियों को सीसीएल के पिपरवार क्षेत्र में उनके कार्यकुशलता को और निपुण करने हेतु प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

सीसीएल के सीएमडी गोपाल सिंह ने सुरक्षा प्रशिक्षुओं को शुभकामनाएं देते हुए कहा है कि "यह टाई-अप सीसीएल सुरक्षा कर्मियों के बेहतर प्रशिक्षण का मार्ग प्रशस्त करेगा, जिसमें वे कार्यस्थल पर बेहतर तरीके से सुरक्षा संबंधी सभी बिन्दूओं पर कृतसंकल्प होकर सामना कर सकेंगे और पेशेवर तरीके से सीसीएल के सुरक्षा कार्य को और मजबूती और बल मिलेगा।

इस प्रशिक्षण का उद्देश्य सीसीएल में नवनियुक्त सुरक्षा कर्मियों के बीच सकारात्मक सैन्य प्रभाव को सुनिश्चित करना है ताकि वे विभिन्न कोयला खदानों और संबंधित क्षेत्रों में बेहतर रूप से सुरक्षा के क्षेत्र में कंपनी को सेवा दे सके। सीसीएल के पिपरवार क्षेत्र में प्रशिक्षण कर रहे सुरक्षा कर्मियों को मेस, बोर्डिंग और ठहरने की व्यवस्था की गयी है।

वर्तमान में सीआईएसफ के विशेषज्ञ अधिकारियों द्वारा 42 सुरक्षा प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहे हैं। यह प्रशिक्षण 14 मार्च, 2020 को समाप्त हो रहा है प्रशिक्षण के दौरान सुरक्षा कर्मियों को आंतरिक और बाह्य सभी तरह की नयी जानकारियों के साथ प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। प्रशिक्षण के उपरांत इन्हें सीसीएल के विभिन्न क्षेत्रों में पदस्थापित किया जायेगा।

घर की स्थिति बेहतर करने के जुनून से सबके लिए बनीं मिसाल

देवघर : जिले के सारवां प्रखंड के सदानंद गांव की महिला पिंकी देवी ने सब्जी की खेती कर दूसरे महिलाओं के लिए एक मिसाल पेश की है। घर की स्थिति को बेहतर करने के जुनून ने पिंकी देवी को मां ने दुर्गा आजीविका सखी मंडल से जोड़ दिया। स्वयं सहायता समूह से जुड़ने के बाद पिंकी ने प्रशिक्षण प्राप्त कर पहले 1000 और 1500 रुपये का ऋण लेकर सब्जी की खेती करनी शुरू की। इससे हुए मुनाफे से उनका आत्मबल बढ़ा। जेएसएलपीएस के द्वारा सीसीएल की मदद से उन्हें 10,000 रुपये का ऋण भी आसानी से मिल गया। इससे वे अपने सब्जियों के व्यापार को आगे बढ़ाकर अच्छी आमदनी कर रही हैं। अब पिंकी सब्जियों के साथ-साथ मटर की खेती भी कर रही है। पिंकी कहती है कि पहले कभी खेती के बारे में नहीं सोचती थी, लेकिन परिस्थितिवश जब काम करने की नौबत आई तब मन लगाकर घर पर ही खेती की। स्वयं सहायता समूह से जुड़ने के बाद आज मैं स्वय पैसे कमा कर अपने घर में सहयोग कर रही हूं।महिलाओं को सशक्त व स्वाबलंबी बनाने के उद्देश्य से उपायुक्त नैंसी सहाय के निर्देश पर जेएसएलपीएस द्वारा सखी मंडल की महिलाओं को प्रशिक्षित कर उन्हें स्वरोजगार से जोड़ा जा जा रहा है। उपायुक्त ने कहा है कि सभी नागरिक एवं हर वर्ग के लोग जैसे बच्चे-बड़े, महिलायें -पुरुष, युवा-बुजुर्ग छोटे से बड़े स्तर पर जैविक कृषि-बागवानी से जुड़कर एक कदम स्वच्छता और हरियाली की ओर बढ़ा सकते हैं। उन्होंने कहा कि स्वयं सहायता समूह से जुड़ने के बाद दीदी की आर्थिक स्थिति बेहतर हीं नही हुई, बल्कि वे अपने साथ-साथ परिवार के लोगों के भी जीवनस्तर में सुधार लायी हैं। इसका जीता-जागता उदाहरण पिंकी देवी हैं, जो अपने लग्न, मेहनत और सफलता से अन्य सभी महिलाओं को भी प्रेरित कर रही है।

आदिवासियों की पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था को और मजबूत करेगी सरकार: हेमन्त सोरेन

संवाददाता

- मानकी मुंडा संघ कोल्हान पोड़ाहाट केंद्रीय समिति के प्रतिनिधियों ने आज मुख्यमंत्री आवास में मुख्यमंत्री से मुलाकात कर सौंपा मांग पत्र
- कोल्हान क्षेत्र में कोल्हान स्वशासन परिषद के गठन की मांग मानकी मुंडा संघ ने रखी
- मालगुजारी वसूली, परती भूमि बंदोबस्ती और विकास का पारंपरिक अधिकार मानकी मुंडा के यथावत रखने की मांग से भी मुख्यमंत्री को मानकी मुंडा संघ ने अवगत कराया

मुख्यमंत्री आवास, रांची :मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने कहा कि आदिवासियों की पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था को और मजबूत किया जाएगा। मुख्यमंत्री आवास में आज मुलाकात करने आए मानकी मुंडा संघ , कोल्हान पोड़ाहाट केंद्रीय समिति के प्रतिनिधियों को मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया कि इस दिशा में सभी आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। इस मौके पर संघ की ओर से मांग पत्र सौंपा गया। उन्होंने मुख्यमंत्री से कोल्हान में कोल्हान स्वशासन परिषद का गठन और मंत्रिमंडल में 'हो' समुदाय के विधायक को शामिल करने की मांग रखी '

जनजातीय भाषाओं के लिए स्वतंत्र एकेडमी बनेगी

मुख्यमंत्री ने कहा कि जनजातीय भाषाओं के लिए स्वतंत्र एकेडमी बनाने पर सरकार विचार कर रही है ,ताकि इन भाषाओं के विकास की राह प्रशस्त हो सके। उन्होंने कहा कि जनजाति समुदाय की कला, संस्कृति परंपरा और भाषाओं को संरक्षित करने के प्रति सरकार कृत्संकल्प है '

'हो' भाषा को आठवीं अनुसूची में शामिल करने के लिए केंद्र को भेजी जाएगी अनुशंसा

मानकी मुंडा संघ द्वारा 'हो' भाषा को आठ-वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग पर मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे संबंधित प्रस्ताव को विधानसभा में पेश किया जाएगा और स्वीकृति मिलने के बाद केंद्र सरकार को जाएगी।

जनजातीय परामर्श दात्री परिषद के लिए बनाई जाएगी नियमावली

मानकी मुंडा संघ द्वारा जनजातीय परामर्शदात्री परिषद का अध्यक्ष आदिवासी को बनाने की मांग पर मुख्यमंत्री ने कहा कि इस परिषद का अब तक नियमावली नहीं बन पाया है। इस दिशा में सरकार जल्द ही आवश्यक पहल करेगी। इस मौके पर संघ ने जनजातीय परामर्श दात्री परिषद की सहमति के बाद ही कोई भी राज्यादेश जारी करने की मांग रखी। मुख्यमंत्री ने मानकी मुंडा संघ को आश्वासन दिया कि कोल्हान पोड़ाहाट क्षेत्र में मानकी और मुंडा के बंदोबस्ती का अधिकार यथावत रहेगा। इसमें किसी तरह की छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि मालगुजारी वसूली, परती भूमि बंदोबस्ती और विकास का पारंपरिक अधिकार मानकी मुंडा के पास से पहले जैसा ही रहेगा।

ईचा खरकई बांध का निर्माण कार्य रोकने की मांग

मानकी मुंडा संघ द्वारा ईचा खरकई बांध का निर्माण कार्य रोकने की मांग पर मुख्यमंत्री ने कहा कि इस दिशा में आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। बांध की वजह से किसी का नुकसान नहीं होने दिया जाएगा इसके साथ ही पर्यावरण संरक्षण का भी ख्याल अनिवार्य रूप से रखा जाएगा । मुख्यमंत्री से मुलाकात करने वालों में मानकी मुंडा संघ के अध्यक्ष गणेश पाट पिंगुआ, रैमुल बानरा, कैलाश बिरुआ सोमनाथ पाडया डेमका सोया, प्रताप सिंह कलूंडिया मनोहर लाल गोड्सोरा धनुंजय देवगम मुंडा , दूधनाथ तियू , रामेश्वर सिंह कुंतिया , सिंहभूमआदिवासी समुदाय के अध्यक्ष दामोदर सिंकु, डॉक्टर दमयंती सिंकू ,सुषमा विरुली , राजेंद्र नाथ पूर्ति रोशन पाट पिंगुआ , डॉक्टर नरेंद्र कुदाद (रजिस्ट्रार, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय) , दीपा मिंज और प्रकाश लागुरी मौजूद थे।

सोने के भंडार में है सांपों का बसेरा

उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में गुरुवार को मिले सोने के भंडार ने दुनियाभर को चौंका दिया था। पहले भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण की एक रिपोर्ट के मुताबिक, यह सोना करीब 3,000 टन था, जो लेकिन बाद में इस दावे को खारिज कर दिया गया है और अब वहां कुछेक क्विंटल सोने का भंडार है ऐसा बताया जा रहा है। नेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि सोने के भंडार के अलावा यहां दुनिया के सबसे जहरीले सांप भी रहते हैं, जो पल भर में इंसान को मौत की नींद सुला सकते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक, सोनभद्र की पहाड़ियों में रसेल वाइपर, कोबरा और करैत का बसेरा है। सांप की ये तीनों ही प्रजातियां दुनिया के सबसे जहरीले सांपों में से मानी जाती हैं। कहा जाता है कि ये इतने जहरीले होते हैं कि अगर किसी इंसान को काट लें तो उसे बचाना मुश्किल हो जाता है। रसेल वाइपर के बारे में तो कहा जाता है कि यह उत्तर प्रदेश में सिर्फ सोनभद्र जिले में ही पाया जाता है। यहां के कई गांवों में यह सांप समय-समय पर दिखता रहा है। दरअसल, इसका जहर हीमोटॉक्सिन होता है, जो खून को जमा देता है। अगर यह सांप काटने के दौरान अपना पूरा जगह इंसान के शरीर में डाल दे तो एक घंटे से भी कम समय में उसकी मौत हो सकती है और अगर जहर कम हो जाए तो भी उस जगह पर घाव हो सकता है।

शिवरात्रि महोत्सव धुम-धाम से सम्पन्न हुई

रांची : श्री सर्वेश्वर महादेव शिव बारात आयोजन समिति हेसल, के तत्वावधान में शिव बारात झांकी महोत्सव श्री सर्वेश्वर महादेव मंदिर हेसल से धुम-धाम से बाजे-गाजे के साथ जीवन्त झांकी निकाली गई। इस झांकी में विशिष्ट अतिथि सांसद संजय सेठ, विधायक सी.पी.सिंह, पुर्व महिला आयोग अध्यक्ष महुआ मांझी, समाजसेवी, आदित्य विक्रम जायसवाल, निशी जायसवाल, पुर्व पार्षद सुनीता देवी, भरत काशी, शैलेश्वर दयाल सिंह, उतम यादव, नीलम शर्मा, प्रिया कुमारी गुप्ता, नम्रता चैधरी, जय सिंह यादव, विक्की यादव आदि-आदि गणमाण्य बन्धुगण भी शामिल होकर शोभा बढ़ाऐ। झ-ांकी रातु रोड काली मंदिर, किशोरी सिंह यादव चैक, पिस्कामोड़ विश्वनाथ शिवमंदिर, भ्रमणकर पुन: हेसल स्थित श्री सर्वेश्वर महादेव मंदिर में प्रसाद वितरण एंव स-ांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ समापन्न हुई। पिस्कामोड़ श्री विश्वनाथ शिव मंदिर में शैलेश्वर दयाल सिंह के नेतृत्व में मिठाई खिलाकर एवं माला पहनाकर बारातियो का भव्य स्वागत किया गया।

इस महोत्सव को सफल बनाने में मुख्य संरक्षक-लाल संजयनाथ शाहदेव, संरक्षक रविन्द्र सरियार, गुरूवचन शर्मा, राजेश्वर सिंह, मुख्य आयोजन प्रभारी- बिनोद कुमार स-ाहु, अध्यक्ष-नीरज कुमार, महासचिव-प्रवीण सिंह, मिडिया प्रभारी-शिव किशोर शर्मा, कार्यकारी अध्यक्ष दिनेश प्रसाद गुप्ता, उपाध्यक्ष अनिल गुप्ता, मुकेश झा, पुजा प्रभारी अविनाश मिश्रा, किशोर महापात्रा, कोषाध्यक्ष अशोक श्रीवास्तव, रागिणी देवी, संध्या देवी, रजनी रंजन, अनिता कुमारी, चन्द्रकान्ता गुप्ता, अंजना प्रियर्दशनी, नीलम किरण, पुष्पा देवी, रिंकी सिंह, इंदु सिंह, उर्मिला देवी, पुष्पा देवी,सहित सम्पुर्ण श्री सर्वेश्वर महादेव शिव बारात आयोजन समिति परिवार ने मुख्य भुमिका निभाई।

अखबार के स्वामी सन कम्युनिकेशन के लिये प्रकाशक मनोरंजन सिंह द्वारा प्रकाशित तथा मेसर्स डी. बी. कॉर्प लिमिटेड,प्लॉट नं535 एवं 1272 ललगुटवा पुलिस स्टेशन, रातू, रांची (झारखंड) से मुद्रित और सन कम्युनिकेशन,अपोजिट कब्रिस्तान गेट नं.-2, टीवीएस गली, रातू रोड, रांची-834001 (झारखंड) से प्रकाशित। संपादकः एम.के.शर्मा * (पी.आर.बी. अधिनियम के तहत खबरों के चयन के लिये उत्तरदायी)आर.एन.आइ. पंजीयन क्रमांक : JHAHIN/2019/78094, email:greenrevolt2019@gmail.com. ☎ 0651-2283018, 8539978825, 8825374626. समस्त विवाद रांची न्यायालय के अधीन होंगे।